चिंतन

'बुलडोजर एक्शन' पर रोक सराहनीय फैसला

देश में कई वर्षों से जारी बुलडोजर एक्शन (बुलडोजर 'जस्टिस') पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से कानून के राज पर भरोसा और बढ़ेगा। शासन व प्रशासन के एक अंग द्वारा संगीन जुर्म के आरोपियों या दोषियों के खिलाफ अतिक्रमण को आधार बनाकर लंबे समय से 'बुलडोजर एक्शन' को अंजाम दिया जा रहा था। इस एक्शन को अपराध के खिलाफ कार्रवाई के रूप में सरकार के पदेन लोगों की ओर से प्रचारित भी किया जा रहा था, इसके आधार पर राजनीति की भी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाकर कार्यपालिका को उसके अधिकार की सीमा बता दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है, कार्यपालक अधिकारी आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। दरअसल, भारतीय कानून में आरोपी को आम नागरिकों की तरह मौलिक, संवैधानिक व कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। अगर कोई अपराधी है तो भी न ही उसका घर गिराया जा सकता है और न ही उसके परिवार का उत्पीड़न किया जा सकता है। हाल के वर्षों में कई स्थानीय प्रशासन व सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, दिल्ली, असम आदि राज्यों में बुलडोजर एक्शन के मामले सामने आए हैं। इस हिसाब से उच्चतम न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कार्यपालक अधिकारी किसी नागरिक का घर मनमाने तरीके से सिर्फ इस आधार पर गिराते हैं कि उस पर किसी अपराध का आरोप है तो यह कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। किसी का घर छीनना मौलिक अधिकार का हनन है। आरोपी एक व्यक्ति है तो पूरा परिवार दोषी कैसे हो सकता है? अदालत ने दिशानिर्देश दिए हैं कि कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ढहाने की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अपील का समय देना होगा, फिर केस में भी खाली करने का समय देना होगा। ध्वस्तीकरण या तो स्थानीय नगरपालिका के नियमों के अनुसार निर्धारित समय पर उठाए जाएंगे या फिर नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों के संबंध में अदालत के निर्देश लागू नहीं होंगे। अदालत के फैसले से साफ है कि सड़क और फुटपाथ बनाने, रेलवे लाइन निर्माण को लेकर किसी अनधिकृत स्ट्रक्चर को गिराया जाता है तो उस पर यह फैसला लागू नहीं होगा। किसी नदी या जलाशय के किनारे अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है या फिर किसी कोर्ट के आदेश से ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है तो भी कोर्ट का निर्देश वहां लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किया है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी 'डिक्री' या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक आदेश जारी कर देशभर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। इमारत को ध्वस्त करने वाले बुलडोजर का भयावह दृश्य अराजकता को याद दिलाता है। हमारे संवैधानिक लोकाचार इस तरह के कृत्य के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देते हैं। इस तरह से संपत्तियां ध्वस्त करने वाले सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अवैध निर्माण के लिए भी जिम्मेदार अधिकारियों को कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए।

कॉप-29 सम्मेलन
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

ब्रह्मांडीय सुरक्षा प्राथमिक एजेंडा बने

कॉप सम्मेलनों का महत्व सभी पक्षों को एकजुट करने की उनकी शक्ति में है। यद्यपि कई बार इनमें लिए गए निर्णय जलवायु संकट से निपटने में उतने कामयाब नहीं हो पाते, जितनी उम्मीद की जाती है किन्तु अच्छी बात यह है कि अपनी-अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए देश एकत्रित होते हैं और चुनौतियों को चिन्हित करने की कोशिश करते हैं। इस बार का कॉप दो भागों में बांटा हुआ था- ग्रीन ज़ोन और ब्लू ज़ोन। कॉप-29 के अध्यक्ष देश द्वारा ग्रीन ज़ोन संचालित हुआ जिसमें आम जनता के लिए खुली प्रतिभागिता का अवसर था और दूसरा ब्लू ज़ोन, जिसके जिम्मे प्रबन्धन का काम था और यह ज़िम्मा संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं ले रखा था।

साल 2015 याद होगा जब एक ऐतिहासिक जलवायु समझौता पेरिस में हुआ था, जिसमें देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने पर सहमति बनाई थी। यह भी कहा गया था कि इसे 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का प्रयास हम समस्त देश करेंगे। कॉप सम्मेलनों का महत्व सभी पक्षों को एकजुट करने की उनकी शक्ति में है। यद्यपि कई बार इनमें लिए गए निर्णय जलवायु संकट से निपटने में उतने कामयाब नहीं हो पाते, जितनी उम्मीद की जाती है किन्तु अच्छी बात यह है कि अपनी-अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए देश एकत्रित होते हैं और चुनौतियों को चिन्हित करने की कोशिश करते हैं। इस बार का कॉप दो भागों में बांटा हुआ था- ग्रीन ज़ोन और ब्लू ज़ोन। कॉप29 के अध्यक्ष देश द्वारा ग्रीन ज़ोन संचालित हुआ जिसमें आम जनता के लिए खुली प्रतिभागिता का अवसर था और दूसरा ब्लू ज़ोन, जिसके जिम्मे प्रबन्धन का काम था और यह ज़िम्मा संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं ले रखा था।

इस कॉप-29 में ऐसी कई बातें प्राथमिकता से रखी गयी हैं यथा उत्सर्जन में कटौती के लिए आपात क़दम उठाए जाएं। हर वर्ष उत्सर्जन में 9 फ़ीसदी की कमी लानी होगी और 2030 तक 2019 के स्तर की तुलना में 43 प्रतिशत गिरावट लाना जरूरी है। कहा जा रहा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के लिए यह सबसे स्पष्ट रास्ता है। इसके साथ ही महासचिव की ओर से यह अपील की गई है कि जलवायु संकट की तबाही से लोगों की रक्षा करने के लिए और अधिक उपाय किए जाने होंगे। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढलने, अनुकूलन आवश्यकताओं और मौजूदा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में एक बड़ी खाई है, जोकि 2030 तक बढ़कर 359 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इस क़िल्लत की कमी का असर आम लोगों के जीवन, फसलों और विकास पर हो रहा है और इसलिए जलवायु वित्त पोषण का स्तर बढ़ाना जरूरी है। सबसे अहम बात, वित्त पोषण के लिए एक नए लक्ष्य पर सहमति बनानी होगी, जिसमें रियायती दरों पर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना होगा और बहुपक्षीय विकास बैन्कों की कर्ज देने की क्षमता में वृद्धि करनी होगी। यह स्पष्ट करना होगा कि सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों को किस तरह विकासशील देशों की मदद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना अहम होगा। कॉप29 के मंच से संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कई गंभीर बातें की जिसमें यदि उत्सर्जन में गिरावट और अनुकूलन में वृद्धि नहीं हुई, तो हर अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर इसका दंश झेलना होगा, इसे देशों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यह गंभीर विषय देशों को समझ आए या न आए लेकिन विभिन्न अकादमिक व जलवायु संबंधी पड़ताल चौकाने वाले आंकड़े दे रहे हैं जिससे कॉप देशों की नींदें हराम हो गई हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर यूएन शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वभर में 12 करोड़ से अधिक लोग जबरन विस्थापन का शिकार हैं, जिनमें से तीन-चौथाई लोग उन देशों में रह रहे हैं, जोकि बढ़ते उत्सर्जनों के असर का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि क़रीब 50 फ़ीसदी विस्थापित उन स्थानों पर हैं, जिन्हें जलवायु

जोखिमों और हिंसक टकराव, दोनों की मार झेलनी पड़ रही है, जिसमें इथियोपिया, हैती, म्यांमार, सोमालिया, सूडान व सीरिया जैसे भूभाग शामिल हैं। कॉप29 ने यह चिंता जाहिर की है कि शरणार्थी समस्याओं से जलवायु समस्याओं को जोड़कर देखा जाना चाहिए और इस पर कारगर कदम उठाए जाने चाहिए।

जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील देशों की सहायता के लिए यह जरूरी है कि जलवायु हानि व क्षति कोष में योगदान का स्तर बढ़ाएं। नए जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य पर सहमति बनाते हुए कई बार पिछले कई सम्मेलनों में यह कहा गया कि सभी देशों के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और सहनसक्षम समुदायों के निर्माण के लिए पर्याप्त साधन व संसाधन उपलब्ध, ऐसा मकैनिज्म तैयार हो लेकिन इस बार भी सभी ने केवल इसी बात को दुहराया है। इसका मतलब यह हुआ कि गंभीरता जितनी दिखानी चाहिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मुद्दे पर, उतनी गंभीरता है नहीं। विश्व में गर्म होती पृथ्वी और खौलते समुद्र के साथ ग्रीन हाउस गैस की भयावहता को समझने में यदि देशों के नेतृत्व गंभीर नहीं होंगे तो पृथ्वी के जीवन की सततता कब तक रहेगी, यह कह पाना कठिन होगा। ऐसे में, महत्वाकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं को मज़बूत करने, जलवायु विज्ञान प्रगति और संकट के दौरान मानव गतिविधि को सुदृढ़ करने, निर्णायक क़दम उठाकर स्वच्छ तकनीकों में निवेश करने और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन के साथ इस जलवायु मुद्दे पर अधिक धन निवेश करने की कोशिश आज पूरे पृथ्वी के लोगों की अपेक्षा बनी हुई है। उफ़नते तूफ़ानों से ध्वस्त होते घर, जंगलों में आग लगने से बर्बाद होते वन, भूमि क्षरण की चुनौतियां, सूखे के कारण नुक़सान, बाढ़, चक्रवात के ख़तरों से बचाव की पुकार आम जनमानस से हो रही है लेकिन बुनियादी ढांचों की जो अपेक्षाएं हैं, वे कैसे तैयार होंगी? क्या अब हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे भविष्य की ओर धकेलने जा रहे हैं, जो उनके जीवन व स्वप्न को अंधकार के साथ मिलने वाला है? दुनिया के विकास के मापदंड आखिर ऐसी दिशा में एक साथ क्यों नहीं सोचकर रणनीति बना रहे हैं जो हमारे जल, जन, वन के लिए हितकारी हो और तापमान कम करते हुए ब्रह्माण्डीय संतुलन के लिए हो, सवाल यह है। दुनिया के राज्यों के समस्त विकास की संकल्पनाएं यदि ऐसी कार्रवाइयों से जी चुरायेंगी तो वे जितने भी कल्याणकारी होने के दावे कर रहे हों, वे सब असत्य ही होंगे और फलीभूत नहीं होंगे।

कचरे के निराकरण से भी राज्य जूझ रहे हैं। समस्त दारोमदार विकासशील और अविकसित राष्ट्रों पर डाल देने से भी किसी की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो जाती। यह एक दिखावा है या छल है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की जगह दूसरों पर आरोप लगाते रहें। विश्व में सबसे ज्यादा हानि इसी वजह से हो रही है, चाहे देश व देशों के नेतृत्व मानें या न मानें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम-यूएनईपी की ओर से कहा गया कि कॉप-29 वार्ता के निर्णायक लक्ष्य यही होंगे कि जलवायु वित्त पोषण के लिए एक सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किया जाए और ब्राजील में 2025 में जलवायु सम्मेलन कॉप-30 जब हो तो उस सम्मेलन को दृष्टिगत अनुकूलन के लिए जलवायु संकल्प लिया जाए। यह ठीक बात नहीं है कि जो जिम्मेदार लोग इकट्ठा होते हैं वे अंत में संकल्प के साथ समापन कर पाने कारस्ते हो लेते हैं। ऐसे में, अब तो विश्व में अर्थदंड या कोई दंड के लिए भी आम सहमति बननी चाहिए, उन देशों के लिए जो संकल्प के साथ वापस होकर यथोचित परिणाम भी देने में अक्षम रहते हैं। समाधान तो पृथ्वी के लोगों को ही खोजना है चाहे जितना भी देरी कर लें, प्रकृति अपने निर्णय में देरी नहीं करेगी, यदि विनाश के ही रास्ते पर हम चलते रहे।

(लेखक शेयर प्रोफेसर पंजाब केंद्रीय विवि है, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

जयंती विशेष

कृष्ण प्रताप सिंह

चीन से शिकस्त ने नेहरू को बुरी तरह तोड़ डाला था

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अपने जीवन के आठ साल, ग्यारह महीने और सात दिन अंग्रेजों की जेलों में बिताने वाले पं. जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब भी चर्चा हो, यह जरूर कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद वे 16 साल प्रधानमंत्री रहे और 'आधुनिक भारत के निर्माता' कहलाये। लेकिन उनके सदमे से भरे अंतिम (खासकर 1962 के चीनी हमले में अपमानजनक पराजय के बाद के) दिन कैसे बीते और 27 मई, 1964 को अपने निधन से पहले उन्होंने कितनी तकलीफें झेलीं, इस बाबत कम ही बात होती है। अलबत्ता, बीबीसी संवाददाता रेहान फजल ने दो साल पहले उनकी पुण्यतिथि पर प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा था कि '1962 में चीन से हुई लड़ाई ने उनको तोड़कर रख दिया था और उसके सदमे से वे कभी उबर नहीं पाये।' परिणाम यह हुआ कि 'उनकी पुरानी शारीरिक ताकत, बौद्धिक कौशल और नैतिक चमक बीते दिनों की बात हो गई और वे निराश व थके हुए से दिखने लगे। उनके कंधे झुक गये और उनकी आंखें भी सोई-सोई सी दिखने लगीं। उनकी चाल में जो तेजी हुआ करती थी, वह भी लुप्त हो गई।' 1964 आते-आते उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं और गम्भीर हो गईं। इसके बावजूद वे भुवनेश्वर में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने गये। सम्मेलन के कार्यक्रम में आठ जनवरी, 1964 को उन्हें बोलना था, लेकिन इसके लिए पुकारे जाने पर वे उठे तो डगमगाकर सामने की तरफ इस तरह गिर पड़े कि उठ नहीं पाये। तब वहां उपस्थित उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने सम्मेलन के स्वयंसेवकों व नेताओं के सहयोग से उन्हें उठाया और संभाला। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उनके शरीर का बायां हिस्सा पक्षाघात का शिकार हो गया है। डॉक्टरों की भरसक कोशिशों के बावजूद उन्हें इतना स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सका कि वे अपना स्थगित भाषण देने दोबारा सम्मेलन में जा सकें। 12 जनवरी को वे लस्त-पस्त से नई दिल्ली लौट आये तो डॉक्टरों ने उनसे कहा कि बेहतर होगा कि वे दोपहर में भी थोड़ी देर सोने की आदत डाल लें। आम तौर पर वे रोजाना 17 घंटे काम करते थे। दोपहर में सोने के लिए उन्हें इनमें पांच घंटों की कटौती करनी पड़ी। उन्हें इसका लाभ भी मिला। 26 जनवरी तक उनका स्वास्थ्य इतना सुधर गया कि वे गणतंत्र दिवस समारोह में सुभीते से भाग ले पाये। लेकिन जल्दी ही उनकी शक्ति फिर क्षीण होने लगी, जिसके चलते फरवरी में आयोजित संसद के उस साल के पहले सत्र में वे बैठे-बैठे ही भाषण देने को विवश हुए। फिर भी उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया और गर्मियों तक इतनी शक्ति संचित कर ली कि किसी का सहारा लिए बिना सामान्य दिनचर्या निपटा सकें।

यह उनका आत्मविश्वास ही था कि अपने निधन से महज पांच दिन पहले 22 मई को एक संवाददाता सम्मेलन में (जो उनके जीवन का अंतिम संवाददाता सम्मेलन सिद्ध हुआ) पत्रकारों के बार-बार 'नेहरू के बाद कौन?' पूछने पर उन्होंने झिड़कते हुए से कह दिया कि 'मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं।' लेकिन दबे पांव आई मौत ने उनके इस दावे को गलत सिद्ध करके ही दम लिया। उक्त संवाददाता सम्मेलन के अगले दिन वे बेटी इंदिरा के साथ छुट्टी मनाने देहरादून चले गये और 26 मई को लौटे तो जरूरी कामकाज निपटाकर नींद की गोली खाई और सो गये। लेकिन सुबह आंखें खुलीं तो पाया कि उनकी पीठ में बहुत दर्द है। सूचना पाकर डॉक्टर उनके पास पहुंचे तो उनकी हालत गम्भीर हो गई थी। जब तक डॉक्टर कोई उपचार करते, वे बेहोश हो गये। बाद में पता चला कि उनकी बड़ी धमनी फट गई है और पउन्हें फौरन खून चढ़ाना पड़ेगा। जब तक खून चढ़ाया जाता, वे कोमा में चले गये। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इसी बीच उन्हें एक और पक्षाघात हुआ, जिसके बाद हृदयाघात से भी गुजरना पड़ा। इसके बाद उन्हें होश में लाने का कोई भी चिकित्सीय उपाय कारगर नहीं सिद्ध हुआ और कोमा में ही दोपहर बाद एक बजकर चवालीस मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ले ली। आकाशवाणी ने दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर देश को उनके निधन की खबर दी तो पूरे देश में शोक की लहर छा गई। गौरतलब है कि उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि उनकी अन्त्येष्टि में किसी भी धार्मिक रीति रिवाज का पालन न किया जाये, लेकिन 29 मई को वह हिन्दू रीति से ही सम्पन्न की गई। वैदिक मंत्रोच्चार और 'द लास्ट पोस्ट' के बिगुलवादन के बीच उनके 17 साल के नाती संजय गांधी ने उन्हें मुखाग्नि दी। बाद में उनकी वसीयत के अनुसार उनकी अस्थियों को भारतीय वायुसेना के विमानों से देश के सभी राज्यों में गिराया गया-खासकर उन खेतों में जहां किसान काम करते थे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

कृष्ण योग के सूत्र

संकलित
दर्शन

भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार सिर्फ शरीर का नियमन ही योग नहीं है, बल्कि आत्मा के साक्षात्कार के लिए किया गया हरेक प्रयास योग की श्रेणी में आता है। इसी कारण श्रीकृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है । वे जनक हैं योग के, धाराएं बहती हैं उनसे योग की, बस जिसको जो आयाम स्पर्श करता है, वह उस आयाम पर अग्रसर हो जाता है। आप जिस योग को योग मानते है, वह पतंजलि योग है। पतंजलि सबसे बड़े वैज्ञानिक है अंतर्जगत के। उनकी पहुंच एक वैज्ञानिक मन की है। उनके पास वैज्ञानिक मस्तिष्क है, लेकिन उनकी यात्रा भीतरी है। किंतु हमारे कृष्ण योगेश्वर हैं । वे दृष्टि देते हैं, स्वतंत्रता देते है, प्रेम और करुणा से आपको भरते है। वे जिससे आपको भरते हैं, वे वह स्वयं ही हैं, इसीलिए कृष्ण का योग धारा बन जाता है, आपसे आपको मिलता है और एक दिन केवल वही ही बचते हैं, आप उनमें मिल जाते हैं। कृष्ण कृष्ण के योग के पहलू जो केवल हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, पर वे सूत्र हैं कृष्ण-योग के 'तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम' अर्थात इससे समत्वबुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करो, यह समत्वबुद्धि-रूप योग ही कर्मों में चतुरता है। अर्थात कर्मों में कुशलता को ही योग कहते है। कृष्ण तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं- अकर्म, कर्म और विकर्म। कर्म वे उसे कहते हैं, सिर्फ करने को ही कर्म नहीं कहते। अगर करने को ही कर्म कहें, तब तो अकर्म में कोई जा ही नहीं सकता। फिर तो अकर्म हो ही नहीं सकता। कर्म को कृष्ण ऐसा करना कहते हैं, जिसमें कर्ता का भाव है।

शुभ कार्य तत्काल करो

संकलित
प्रेरणा

कोई स्त्री अपने पिता के यहां से लौटी थी, अपने पति से कह रही थी -'मेरा भाई विरक्त हो गया है। वह अगली दीवाली पर दीक्षा लेकर साधु होने वाला है। अभी से उसने तैयारी प्रारंभ कर दी है। वह अपनी संपत्ति की उचित व्यवस्था करने में लगा है।' पत्नी की बात सुनकर पति मुस्कुराया। स्त्री ने पूछा—'तुम हंसे क्यों ? हंसने की क्या बात थी।!' पति बोला-'और तो सब ठीक है, किंतु तुम्हारे भाई का वैराग्य मुझे बहुत अद्भुत लगा। वैराग्य हो गया है दीक्षा लेने की तिथि अभी निश्चित हुई है और वह संपत्ति की उचित व्यवस्था में लगा है।'! भौतिक संपत्ति में बुद्धि और इस उत्तम काम में भी इतनी दूर की योजना! इस प्रकार की तैयारी करके त्याग नहीं हुआ करता। त्याग तो सहज ही हुआ करता है। स्त्री को बुरा लगा वह बोली -'ऐसे ज्ञानी हो तो तुम्हीं क्यों कुछ कर नहीं दिखाते।' 'मैं तो तुम्हारी अनुमति की ही प्रतीक्षा में था।' पुरुष ने वस्त्र उतार दिए और एक धोती मात्र पहने घर से निकल पड़ा। स्त्री ने समझा कि यह परिहास है। थोड़ी देर में उसका पति लौट आवेगा, परंतु वह तो लौटने के लिए गया ही नहीं था। सच है वैराग्य के लिए कोई तिथि नहीं सोची जाती। वैराग्य के लिए मन, कर्म और अपने विचार अपने नियंत्रण में होना जरूरी है। तभी हम वैराग्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

अभी भी मौका है, हम सुधर जाएं

दिल्ली में जानलेवा साबित होते वायु प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय भी गंभीर दिख रहा है। उसने दिल्ली पुलिस को दिल्ली में पटाखे चलाने पर रोक लगाने में नाकामयाब होने पर फटकार लगाई है। लेकिन क्या हम सब डंडे से ही सुधरने वाले है? जब हम सब यह जानते हैं कि सर्दियों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पटाखे भी है तो हम क्यों इन्हें चलाते हैं? सर्दियों में प्रकृति के विरुद्ध जो भी छोटे-छोटे काम किए जाते हैं वो वायु प्रदूषण का कारण भी बनते हैं, क्योंकि शायद सर्दियों में वातावरण में एक कॉल्ड परत बन जाती है जो दूषित हवा को ऊपर नहीं उठने देती, एक दायरे तक सीमित रहती है, और जब तक बारिश न हो तब तक यह प्रदूषित हवा धरती के करीब ही रहती है। इसलिए सर्दियों में त्योहारों या सामाजिक समारोहों में पटाखों का प्रयोग कम से कम, या न ही किया जए तो अच्छा है। - *सुभाष साहू, कांकेर*

ट्रेंड

महिला बटालियन

राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में मंत्री तरवाहर ने सीआरपीएफ की पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। महिला बटालियन को एक विशिष्ट टुकड़ी के रूप में खड़ा किया जाएगा।

-अमित शाह, केंद्रीय मंत्री

किसान परेशान

महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास के किसान भारत की नीतियों के कारण हताश और निराश हैं। अरसी उपज के बावजूद सही दाम नहीं मिलने से सोयाबीन के किसान बेहद परेशान हैं। हम सरकार बनाते ही सही दाम देने के लिए सख्त निर्णय लेंगे

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

जोखिम लेना जरूरी

अमेरिका में 80% से अधिक उद्यमी स्व-निर्मित है और उन्होंने अपना व्यवसाय शून्य से खड़ा किया है। यह जोखिम लेने को प्रोत्साहित करता है और धन सृजन का मार्ग आसान बनाता है।

-अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

सच बोलना होगा

लोकतंत्र दुनिया में है क्योंकि सत्यता सुलझाने वाले और सत्यता झेलने वालों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। कानूनी सत्ताग बनाने के लिए हमें सत्य के साक्षी सच बोलना होगा।

-कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार विजेता

करंट अफेयर

लेबनान से होगा संघर्ष विराम? इजरायली रक्षामंत्री की दो टूक

इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा। इसके साथ ही उसने लेबनान में सीजफायर की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। इजरायली रक्षामंत्री इजरायल काट्स ने कहाकि वह पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। इतना ही नहीं, काट्स ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर भी बयान दे डाला। इजरायल के पूर्व रक्षामंत्री योव गैलेंट के हटने के बाद काट्स ने यह पद संभाला है। बता दें कि हमास पर कार्रवाई में इजरायली सेना के रिसर्वास पर योव गैलेंट और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेद हो गए थे। काट्स इससे पहले इजरायल के विदेश मंत्री थे। उन्होंने कहाकि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, न तो कोई सीजफायर होगा और न ही हिजबुल्लाह को कोई राहत मिलने वाली है। इजरायली सेना जनरल स्टाफ फोरम के साथ मीटिंग में उन्होंने यहां तक कहाकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने अब बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। उन्होंने कहाकि इजरायल के ऊपर मंडरा रहे किसी भी खतरे को जड़ से मिटाने का वक्त आ चुका है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसके पास इजरायल से सीजफायर का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

ऑफ बीट

सप्ताह में 150 मिनट की शारीरिक गतिविधि जरूरी

व्यायाम आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और विशेष रूप से आपके हृदय के लिए अच्छा है। विशेषज्ञों की राय है कि हमें सप्ताह में 150 मिनट की मध्यम-से-जोरदार शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। शोधकर्ताओं ने पाया कि एक्सीलेरोमीटर मूल्यांकन के बाद छह वर्षों में, जो लोग नियमित रूप से मध्यम से जोरदार गतिविधि करते थे, उनमें गतिहीन लोगों की तुलना में स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिल की विफलता और एट्रियल फाइब्रिलेशन कम था। इस अध्ययन का अनोखा निष्कर्ष यह था कि जिन लोगों ने अपनी आधी से अधिक गतिविधि सप्ताहांत में की थी, उनकी तुलना में उन लोगों के परिणामों में कोई अंतर नहीं था, जिन्होंने इसे पूरे सप्ताह में फैलाकर किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कब किया गया था, मध्यम-जोरदार शारीरिक गतिविधि बेहतर हृदय स्वास्थ्य से जुड़ी थी। अध्ययन में, लेखकों ने उन लोगों को 'सप्ताहांत योद्धा' कहा, जिन्होंने सप्ताह में 150 मिनट से अधिक की मध्यम-से-जोरदार गतिविधि की। यह लाइक्रा पहने पहाड़ी रास्तों पर साइकिल की सवारी करते हुए या मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को 90 मिनट की कठिन फुटबॉल खेलने जैसा है।

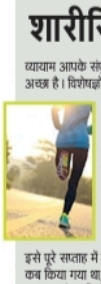

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

सम्पादकीय

मणिपुर में गहरे होते जख्म

मणिपुर जिसका अर्थ है रत्नों की भूमि। पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी एक ऐसी घाटी जिसमें 39 जातीय समुदाय रहते हैं जो हिन्दू, ईसाई और इस्लाम धर्म सहित विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, साथ ही सनमाही जैसी स्वदेशी धार्मिक परम्पराएं भी हैं। मणिपुर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का झंडा सबसे पहले राष्ट्रवादी मुक्ति सेना ने मणिपुर में ही फहराया था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 14 अप्रैल, 1944 को इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर मोइरंग में ध्वज फहराया था। तब उसे दिल्ली का दरवाजा माना जाता था। आज मणिपुर दिल्ली की ओर देख रहा है। पिछले 2 सालों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। जिरिबाम जिले में सीआरपीएफ कैम्प पर हमला करने वाले संदिग्ध उग्रवादियों में से 11 को ढेर कर दिया गया। राज्य में कई जगह बमों से सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला किया गया। एक सप्ताह के भीतर हमार जनजाति की एक महिला से मैतेई विद्रोहियों ने सामूहिक बलात्कार कर जिन्दा जला दिया। मैतेई समुदाय की एक और महिला को कुकी विद्रोहियों ने गोली मार दी। राज्य में लगातार हो रही हिंसा से गृहयुद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हर जगह हिंसा के निशान देखे जा सकते हैं। बम के टुकड़े, धरती पर काली और सफेद राख, जले हुए घर, टिन की छतें और जल चुकी गाड़ियां।

मैतेई और कुकी समुदाय में खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि दोनों समुदाय अपने-अपने गांव में हमलों और गोलीबारी से बचने के लिए बंकर बनाए हुए हैं। ड्रोन और रॉकेट हमलों से बचने के लिए दुरबीनों से नजर रखी जा रही है। पाइपों के जरिये पम्पगन बनाकर रॉकेट दागे जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से जारी हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य में हिंसा थम क्यों नहीं रही? दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सवाल यह भी है कि आखिर दोनों ही समुदायों के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए। हिंसा की शुरूआत तब हुई थी जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विचार करने को कहा, जो मणिपुर में बहुसंख्यक आबादी है। हाईकोर्ट के फैसले से कुकी और नगा स्वदेशी समुदाय में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद हिंसा की शुरूआत हो गई। हालांकि विरोध-प्रदर्शनों को मणिपुर में हिंसा के सबसे तात्कालिक कारण के रूप में पहचाना जा सकता है लेकिन राज्य में कई वर्षों से स्वदेशी समुदाय के बीच तनाव बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा स्वदेशी भूमि अधिकारों के मुद्दों को संभालने के तरीके को मुख्य रूप से राजधानी घाटी के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों को लक्षित करने के रूप में देखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में आरक्षित वनों का सर्वेक्षण करने के प्रयासों को अफीम की खेती को कम करने का प्रयास बताया गया था लेकिन इसके परिणामस्वरूप कुकी गांवों में बेदखली हुई है। इस बीच, विवाद का एक अन्य मुद्दा स्वदेशी समुदायों के बीच वर्तमान भूमि असंतुलन है। मैतेई लोग पहले उल्लेखित पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि नहीं खरीद सकते हैं लेकिन कुकी और अन्य जनजातीय समुदाय घाटी में भूमि खरीद सकते हैं।

नेहरू को जानना नहीं, समझना भी जरूरी

नेहरू दार्शनिक और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। राष्ट्रवाद, समाजवाद, संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और संसदीय लोकतंत्र पर उनके विचार सुविचारित और स्पष्ट थे। वैचारिक विविधता, वैज्ञानिक मानवतावाद और साम्यवादी चिंतन उनके लिए देश के नवनिर्माण के मानक थे। वह सभी विचारधाराओं और धर्म को साथ लेकर चलते थे। 19वीं-20वीं सदी के उनके इतिहास बोध ने ही पूर्ण स्वराज्य और भारत के भविष्य की अधारभूत कल्पना की थी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के समय अशिक्षा, गरीबी, जाति-धर्म के आधार पर विभाजन और असमानता के बीच महाशक्तियों में शीत युद्ध की समस्याएं भी थीं।

प्रदीप मिश्र

प्रसिद्ध तंत्रिकाविज्ञानी सिगमंड फ्रायड की मान्यता थी कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। यह मनोविश्लेषण, तर्क और विवेचना आजादी के अमृतकाल में अकाट्य सिद्ध हो रही है। इसमें पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति बदनीयती, विद्रूपता, विद्वेष और वैचारिक बदसूरती छिप नहीं रही है। नवनिर्माण के एक कालखंड की सूचनाओं, परंपराओं, घटनाओं और उपायों पर अभिमान के बजाय इन्हें झुठलाने की साजिश अभियान के रूप में हो रही है। इतिहास को विस्मृत कर स्वयं की सर्वश्रेष्ठता का अहम जताने-इठलाने की कोशिश जारी है। ऐसे में संसदीय लोकतंत्र, आर्थिक सहभागिता, आंतरिक और बाह्य समन्वय, वैश्विक संतुलन और सामाजिक समरसता समझने के लिए नेहरू और उनके कार्यकाल की वास्तविकता जानना प्रासंगिक हो गया है। वाद, विवाद और संवाद से समाज को समझने का मंतव्य, पराकाष्ठा के स्तर के प्रयत्न, प्रबंधन और परिश्रम के बूते ही भारत की पृथक पहचान है। स्वातंर्त्य योद्धाओं का त्याग-बलिदान, स्वाधीन भारत के सीमित संसाधनों में सतत साधना और शांति प्रयासों का योगदान है।

आजादी के बाद नेहरू ने विश्व के राजनयिक परिदृश्य के मुताबिक बातचीत कर विकास को गति दी। पंचवर्षीय योजनाएं उनका ही विचार थीं। सोचिए, भाखड़ा नागल और रिहंद बांध उनकी आलोचना का आधार है? आईआईटी और आईआईएम किसके लिए बने? गुट निरपेक्ष आंदोलन की ताकत क्या जी-20 और ब्रिक्स से ही नहीं, नाटो और मौजूदा यूरोपीय यूनियन से कम थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन को नेहरू ने उसी दौर में सकारात्मक शक्ति और संतुलन का केंद्र बनाया था, जब किसी सबल देश का अनुसरण दासत्व के भाव से किया जाता था। नेहरू का नजरिया आयातित नहीं था। वह संकल्प और संघर्ष से हासिल स्वाधीनता के स्वन्विल आकार को धरातल पर आकार देना चाहते थे। इसीलिए उनके लिए समाजवादी, वामपंथी और भारतीय भावनाओं के साथ परंपरागत दर्शन और विचारों को समझना और उसे मध्यमार्ग में राष्ट्रहित-जनहित के लिए ढालना आसान रहा। वह पूंजीवाद के विरोधी नहीं थे लेकिन अच्छी तरह जानते थे कि इसे अधिक प्रोत्साहन से गरीब और मध्य वर्ग की देश की तरक्की में हिस्सेदार होने की आकांक्षा को आघात लगेगा। सार्वजनिक उद्यम, जिन्हें विनिवेश के बहाने आज भी टुकड़ों-टुकड़ों में बेचा जा रहा है, नेहरू के औद्योगिकीकरण और जनभागीदारी की सोच का ही प्रतिबिंब हैं। उन्होंने सबके सहयोग से इनकी संरचना की थी। इसका बड़ा भाग अब भी भारत की सशक्त आर्थिकता का आधार है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के इतिहास की भूमिका को पढ़ेंगे तो जानेंगे। नेहरू साम्राज्यवाद और फासीवाद दोनों को पतनोन्मुख पूंजीवाद के दो चेहरे मानते थे। उन्होंने दोनों के खिलाफ संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का बुनियादी लक्ष्य बताया। नेहरू के कई समकालीन नेता उनसे बेहतर दृष्टि रखते थे लेकिन नेतृत्व क्षमता सिर्फ नेहरू में थी, इसलिए वह ज्यादातर समस्याओं के संघान में सफल होते थे। 1919 से 1921 तक उत्तर प्रदेश के अवध में किसान आंदोलन के नेतृत्व से उनकी नैतिकता और निपुणता सिद्ध हो चुकी थी। हालांकि 1950 में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के साथ अल्पसंख्यकों का पलायन रोकने और अधिकारों के संरक्षण का समझौता किया किंतु 1952 में लियाकत अली की हत्या के कारण उस पर अमल नहीं हो सका। उलटे पाकिस्तान ने इसी दौरान जम्मू-कश्मीर के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। 1954 में चीन के साथ तिब्बत के सवाल पर पंचशील समझौता भी असफल रहा, जबकि 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई के साथ उनकी बातचीत अपने ही सहयोगियों के दबाव और आलोचना के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल, दोनों

पड़ोसियों से दोस्ती के पीछे उनकी सोच थी कि भौगोलिक रूप से निकट निवासियों के साथ रहने की अनिवार्यता नहीं बदली जा सकती, इसलिए उनके साथ संघर्ष को ही सर्वोपरि मानते हैं। समाज को संशय में डाल कर अल्पकाल के लिए तो यह सुविधा हासिल की जा सकती है पर समय की कसौटी पर मार्गदर्शक माने जाने वालों की विश्वसनीयता का ह्रास भी होता है। व्यक्तिगत आक्रमण उसी अवस्था में किए जाते हैं, जब व्यवस्थागत और बुनियादी तंत्र में सुधार के मार्ग में व्यवधानों और बाधाओं की सम्यक समझ का सीमांकन हो जाता है। अनुभव और अभ्यास से अनुमान सहज-स्वाभाविक होते हैं।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और वैचारिक परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वयन के लिए दृष्टि विकसित होती है। यही दिशा देती है। आत्मकथा में उन्होंने लिखा हैं-मुझे राष्ट्रवाद बहुत ही संकीर्ण और अपर्याप्त सिध्दांत लगता था। राजनीतिक आजादी, स्वाधीनता निस्संदेह आवश्यक है परंतु वे सिर्फ सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। सामाजिक आजादी और समाज तथा राज्य की समाजवादी संरचना के बिना देश और व्यक्ति पर्याप्त प्रगति नहीं कर सकता है।

विश्व मंचों पर भारत के अपेक्षित मान की आधारशिला रखने वाले नेहरू पर अथाह लिखा गया है। अब इसे एक बार फिर पढ़ने और समझने की जरूरत है। इसलिए भी, क्योंकि अध्ययन और अनुभव से ऊर्जान्वित अधिकार आधुनिकता के लिए अत्यावश्यक है। आधारभूत परिवर्तन के लिए इन्हीं मूल्यों और आधारों को आत्मसात करना आवश्यक होता है। इसी क्रम में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का विचार उल्लेखनीय है। वह कहते थे-'एक राष्ट्र जो अपने नायकों का सम्मान नहीं करता है, वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा।'

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरकों को पूरा करेंगे। कब आप रात जाकता चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे पौधारे बोए हैं, जब आपके जिंदगे कुसर होंगे और टूटती दवा, आपको सिर्फ बाधों से लाकाम लगा रहेगा। हम ने किसे हमारे ग्रहों में और जीवन सुधी की शुरुआते कहा स्वास्थ्यकर और नई सफलता दर्शाते, वहीं पारिवारिक संबंधों में भी, जहां हम लगभगहम सही संतुलन और कठिनाई से तालमेल पाएंगे।

मेष

अविवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने के योग हैं। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी। मित्रों से लाभ होगा। आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा। मित्रों से लाभ होगा।

वृष

हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए वाणी में गुस्सा ना रखें। परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो, इसका खास ध्यान रखें।

मिथुन

माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी।

कर्क

आप तन-मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आज भाग्य आपका साथ देगा। इनकम बढ़ेगी। परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा। धन लाभ होगा और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं।

सिंह

सरकार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिकूल संयोग के बनने से आपके कार्य में विलंब होगा। शरीर में ताजगी और मन में उत्साह का अभाव रहेगा। पेट के रोग सताएंगे। नौकरी में अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार से आपको दुख होगा।

कन्या

संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आप आज हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे। आज आपको यात्रा ना करने की सलाह दी जाती है।

तुला

मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे। नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं। तन-मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी। अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज आप के घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा।

वृश्चिक

आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कामों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप में आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए आप सावधान ही रहें। संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन अशांत रहेगा।

धनु

बाहर जाना हो सकता है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सरकारी लाभ होगा एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। पहले से निर्धारित काम के लिए आपका प्रयास ज्यादा रहेगा। आपका व्यवहार न्यायपूर्ण रहेगा।

मकर

आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। जरूरी कामों पर धन खर्च होगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दफ्तर में सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा। मित्रों से मुलाकात होगी।

कुंभ

नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे। आपकी पदोन्नति के योग हैं। अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगा। परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी। घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है।

मीन

आज धन का व्यय अधिक होगा। आज आपका दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है और किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा। महिलाओं के मायके से समाचार आने के योग हैं। पानी वाली जगहों से दूर रहें।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार है राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी जितेन्द्र सिंह जी। जी हां गांव गिलाकोर जोधपुर के मूल निवासी हैं और सन 1992 में जन्में जितेन्द्र सिंह अपनी चौथी पीढ़ी में बैल्ट सर्विस में सेना/पुलिस में सेवाए दे रहे हैं। इससे पूर्व इनके पड़दादा बिट्रिश आर्मी में रहे उसके बाद इनके दादाजी इंडियन आर्मी में और बाद में पुलिस में रहे और डीएसपी पद से सेवानिवृत हुए इसके बाद इनके चाचा साब पुलिस में रहे और एडिशनल एसपी पद से सेवानिवृत हुए। वर्तमान में ये डिप्टी एसपी (सीओ)सुमेरपुर पाली लगे हुए हैं। 2019 से राजस्थान पुलिस की सेवा में आए शिक्षा दीक्षा जोधपुर से हुई हैं। 2019 से 2020 आरपीए प्रशिक्षण में रहे इसके बाद 2021 उदयपुर प्रशिक्षण, 2022-2023 सीओ झाड़ोल उदयपुर में सेवाए दी और पुलिस के कैप्ष आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय को चरितार्थ किया। 2024 से वर्तमान सीओ पाली पद को सुशोभित किए हुए हैं। जहां भी रहे वहां के अपने अधिनस्थ कर्मचारी व अधिकारी और अपने उच्चाधिकारियों के साथ बेहतरीन तालमेल से लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। शख्सियत कॉलम के माध्यम से ये युवाओं को नशे से दूर रहने व अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में संपादित करने और लोगों को मोबाईल का दुरूप्रयोग नहीं बल्कि सदुप्रयोग करने का संदेश दे रहे हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

जितेन्द्र सिंह
(डिप्टी एसपी)

रूपक शर्मा

आधुनिक युवा पीढ़ी पर सिनेमा के दुष्प्रभाव

बढ़ता राजस्थान

आधुनिक युवा पीढ़ी पर फिल्मों का दुष्प्रभाव एक गंभीर विषय है, जो उनके मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। फिल्मों का उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना है, लेकिन कई बार फिल्मों में प्रस्तुत की गई हिंसा, अपराध, असामाजिक व्यवहार, और अनुचित जीवनशैली का प्रभाव युवा पीढ़ी पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। यहाँ कुछ मुख्य दुष्प्रभावों का उल्लेख किया गया है

हिंसक व्यवहार-

फिल्मों में बार-बार दिखाई जाने वाली हिंसा से युवा पीढ़ी इसे सामान्य समझने लगती है और कभी-कभी इस प्रकार के व्यवहार को अपना लेती है। यह उनके स्वभाव में आक्रामकता को जन्म देता है।

असामाजिक और अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षण-

फिल्मों में अपराध, चोरी, धोखा, और अन्य अनैतिक कार्यों को कभी-कभी ग्लैमरस तरीके से दिखाया जाता है। इसके चलते युवा इन्हें रोमांचक और सही मान सकते हैं और इस दिशा में आकर्षित हो सकते हैं।

सपनों की दुनिया में जीना-

फिल्मों में दिखाए गए आदर्श जीवन, धन, सफलता और प्रेम कहानियों के कारण युवा वास्तविकता से दूर होकर एक काल्पनिक जीवन जीने लगते हैं। वे वास्तविकता को स्वीकारने में कठिनाई महसूस करते हैं और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

अनुचित जीवनशैली और स्वास्थ्य समस्याएं-

फिल्मों में धूम्रपान, शराब, और नशीली दवाओं का प्रयोग ग्लैमरस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। युवा पीढ़ी इसे देखकर

प्रेरित हो सकती है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

सामाजिक मूल्यों का क्षरण -

आधुनिक फिल्मों में अक्सर परिवार और समाज के मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, जो युवाओं को समाज और परिवार के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है और सामाजिक ढांचे में अस्थिरता आ सकती है।

शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट-

फिल्में देखकर मनोरंजन में ज्यादा समय बिताने के कारण युवाओं का पढ़ाई में ध्यान कम हो सकता है। इससे उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फिल्में, अगर सकारात्मक रूप से बनाई जाएँ और उनका संदेश उचित हो, तो वे समाज पर अच्छा प्रभाव भी डाल सकती हैं। युवा पीढ़ी पर फिल्मों का प्रभाव नियंत्रित करने के लिए माता-पिता और शिक्षकों को भी आवश्यक मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ मानसिकता विकसित कर सकें।

अनिल माथुर
जोधपुर (राजस्थान)

विशेष आलेख

विश्व मधुमेह दिवस पर विशेष : बढ़ते मधुमेह को नियंत्रित करने की वैश्विक चुनौती

ललित गर्ग

डायबिटीज यानी मधुमेह दुनियाभर में तेजी से बढ़ती ऐसी बीमारी है जो अन्य अनेक बीमारियों एवं शरीर की जर्जरता का कारण बनती है, जिसका शिकार हर उम्र के लोगों को देखा जा रहा है। जिन लोगों का शुगर लेवल अक्सर बढ़ा हुआ रहता है उनमें आंखों, किडनी, तंत्रिकाओं, शरीर की सुस्ती और हृदय से संबंधित कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती इस गंभीर और क्रोनिक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने, इससे बचाव को लेकर लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि डायबिटीज के मरीज साल-दर साल बढ़ते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में 53 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी के शिकार हैं और अगले दो दशकों में रोगियों की संख्या 80 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। विश्व मधुमेह दिवस दुनिया की गंभीरतम बीमारियों में से एक होने की वजह से 160 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और अपने जागरूकता अभियानों, उपचार तक बेहतर पहुंच की कवालत और मधुमेह से निपटने के लिए गुणवत्तापूर्ण सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इस वर्ष, इस दिवस की थीम है 'बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना'। यह थीम लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर मधुमेह के प्रभाव पर प्रकाश डालती है और मधुमेह प्रबंधन-नियंत्रण-जागरूकता के महत्व पर भी जोर देती है और यह बताती है कि इसके लिये संतुलित, योगमय एवं गुणवत्ता जीवन कैसे इस बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। दरअसल, विश्व मधुमेह दिवस को 14 नवंबर को मनाने का मुख्य उद्देश्य सर फ्रेडरिक बैंटिंग को याद करना था। 1992 में सर फ्रेडरिक बैंटिंग ने वार्लस बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह फाउंडेशन (आईडीएफ) के अनुसार, 2021 में मधुमेह के कारण 67 लाख लोगों की मृत्यु हुई और अनुमान है कि उसी वर्ष 53.7 करोड़ (10 में से 1) लोग इस बीमारी के साथ जी रहे थे और अनुमान है कि यह संख्या 2030 में बढ़कर 64.3 करोड़ और 2045 तक 78.3 करोड़ हो जाएगी। यह तथ्य सामने आया है कि मधुमेह से प्रभावित 2 वयस्कों में से 1 यानी 44 प्रतिशत, लगभग 24 करोड़ लोग, अभी तक निदान नहीं करा पाये हैं, उनमें से अधिकांश टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं, जिसे कुछ जीवनशैली में बदलाव, इच्छाशक्ति, योग-साधना और स्वस्थ आहार आदतों से रोका जा सकता है। असंतुलित जीवनशैली के कारण लगभग 54.1 करोड़ वयस्कों को टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा है। डायबिटीज के होने एवं पनपने के अनेक कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारक फैमिली हिस्ट्री को माना जाता है। यानी कि यदि माता-पिता या भाई-बहन को टाइप-2 डायबिटीज है तो आपको भी मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। अधिक वजन या मोटापा डायबिटीज रोग के लिए एक मुख्य जोखिम है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अधिक मोटा खाते हैं उनमें पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा रहता है। मोटापा से ग्रस्त लोगों में डायबिटीज की स्थिति हृदय रोग और अन्य जटिलताओं को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। विशेषज्ञ का मानना है कि शारीरिक निष्क्रियता भी डायबिटीज की जोखिम को बढ़ा देती है। शारीरिक गतिविधि जैसे नियमित रूप से योग-व्यायाम वजन और खेलकूद से वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है और इससे ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मधुमेह से बचे रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करें। टाइप-2 डायबिटीज होने का जोखिम उन लोगों में अधिक होता है, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का पता चलता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे अवधि में शुगर के स्तर को कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं। गर्भावधि में मधुमेह के कारण ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा रहता है जिसका असर गर्भवती और बच्चे दोनों की सेहत पर देखा जाता है। डॉक्टर बताते हैं, भले ही दुनियाभर में सबसे ज्यादा मरीज टाइप-2 डायबिटीज के देखे जाते रहे हैं पर मधुमेह चार प्रकार का होता है। इसे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी समझना या युवावस्था में शुगर की समस्या को अनदेखा करना आपके लिए दिक्कतें बढ़ाने वाला हो सकती है। बढ़े रहने वाले शुगर लेवल का असर हृदय और आंखों की सेहत पर भी पड़ सकता है, इसलिए डायबिटीज को हल्के में लेने की भूल नहीं की जानी चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को अपने खाने पीने के अलावा नींद का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। कम नींद के कारण ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है। भोजन और एक्सरसाइज के अलावा नींद भी शरीर के लिए उतनी ही जरूरी होती है। नींद पूरी न होने से शरीर सुस्त हो जाता है और तनाव भी बढ़ता है। ऐसे में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। शरीर में जब शुगर का लेवल बढ़ता या घटता है तो नींद से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को हमेशा पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। यदि आपको देर रात तक जागने की आदत है या फिर आप देर रात तक जागकर काम करते हैं तो आपकी यह आदत आप पर भारी पड़ सकती है। अनियंत्रित मधुमेह हृदय संबंधी समस्याओं, तंत्रिका क्षति, गुर्दे की क्षति, पैर की क्षति, त्वचा संक्रमण, सर्भन दोष, अवसाद, दंत समस्याओं जैसी घातक जटिलताओं को जन्म दे सकता है। विकिस्ता-विज्ञान की अपूर्व प्रगति के बावजूद मधुमेह जैसी जटिल एवं असाध्य बीमारी का राक्षसी-पंजा नियंत्रण से बाहर है, इसलिये व्यक्ति को खुद को खुद के प्रति जागरूक होना होगा। मधुमेह का नियंत्रित करने के लिये योग-ध्यान-साधना-प्रात:भ्रमण की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैज्ञानिक डॉ. थियोयोर ने बहुत पहले अपने अनुसंधान में बताया कि ध्यान एवं योग करने वाले व्यक्तियों की साइकोलॉजी में असाधारण रूप से परिवर्तन होता है। ऐसे व्यक्तियों में घबराहट, उत्तेजना, मानसिक तनाव, उग्रता, मनोकायिक बीमारियां, स्वार्थपरता और विकारों में कमी पाई गयी है तथा आत्मविश्वास, सहनशक्ति, स्थिरता, कार्यदक्षता, विनोदप्रियता, एकाग्रता आदि गुणों में वृद्धि देखी गयी है। ये ध्यान-साधना एवं योग में प्रत्यक्ष लाभ अनुभूत किये गये हैं। इसीलिये मधुमेह को परास्त करने के लिये इन गुणों युक्त जीवनशैली को अपनाया जाना चाहिए। सम्पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ जीवनरूपी प्रयोगशाला में इसे प्रायोगिक रूप देकर जीवन में मधुमेह रूपी-राक्षस को निरस्तत्र करके जीवन में आनन्द का अवतरण किया जा सकता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इयोरूपा रोड खण्डवा,निवाई रोड (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा चतुर्वेद । प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 ठोक कार्यालय-बाईपास निवाई, ठोक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-गेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

संवाद और कूटनीति ही स्थायी शांति की गारंटी देते हैं, न कि सैन्य कार्रवाई। -मार्टिन मैकगिनीज

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े केंद्रीय बैंक के प्रमुख शक्तिकांत दास के अक्तूबर में महंगाई बढ़ने के पूर्वानुमान की ही पुष्टि करते हैं। जुलाई-अगस्त में खुदरा महंगाई कम रहने की वजह से कुछ उम्मीदें जरूर बंधी थीं, लेकिन फिलहाल की स्थितियों में दिसंबर में नीतिगत दरों में कटौती की संभावना कम ही है।

महंगाई और आशंका

बीते अक्तूबर महीने में खुदरा महंगाई का केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा को भी पार कर जाना, जो पिछले चौदह महीनों का उच्चतम स्तर भी है, चिंताजनक है, जो अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव की ओर ही इशारा करता है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास अक्तूबर में महंगाई के बढ़ने की चेतावनी पहले ही दे चुके थे, जो सही ही साबित हुई है। वह यह भी कह चुके हैं कि नीतिगत दरों में बदलाव तभी होंगे, जब महंगाई चार फीसदी के स्तर पर आएगी। महंगाई के भय से ही केंद्रीय बैंक ने पिछले करीब दो वर्षों से नीतिगत दरों में कटौती नहीं की है। बीते जुलाई व अगस्त में खुदरा महंगाई कम रहने की वजह से कुछ उम्मीदें जरूर बंधी थीं, लेकिन पहले सितंबर और फिर अक्तूबर में महंगाई का हाल देखकर, दिसंबर में होने वाली बैठक में भी ब्याज दर घटाए जाने की संभावना धूमिल होती ही दिख रही है। त्योहारों के मौसम में विनिर्माण क्षेत्र के बेहतरीन योगदान से देश में औद्योगिक उत्पादन अगस्त की अपेक्षया सितंबर में बेशक कुछ बढ़ा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए राहत की बात है। लेकिन खुदरा महंगाई चुनौती बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी बाधा खाद्य पदार्थों की महंगाई है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के 9.24 फीसदी से बढ़कर अक्तूबर में 10.87 फीसदी तक पहुंच गई है। दरअसल, मौसम ने जिस तरह से पूरे देश में असामान्य व्यवहार दिखाया है, उससे विभिन्न राज्यों में फसलें प्रभावित हुई हैं। आलू, प्याज और टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियों के उत्पादन में कमी भी खाद्य महंगाई बढ़ने की एक महत्वपूर्ण वजह रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया में आपूर्ति शृंखला में समय-समय पर बाधा पहुंचने से खाद्य तेल की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। दूसरी तरफ, कच्चे तेल के आयात बिल का बढ़ना भी चिंताजनक है, क्योंकि अगर इसकी कीमतें और बढ़ती हैं, तो महंगाई का अलग स्तर पर पहुंचना तय है। हालांकि यह उम्मीद जताई

जा रही है कि नई फसल के आने से महंगाई के समीकरण कुछ बदल सकते हैं। रबी की फसल को लेकर तो संभावनाएं जताई ही जा रही हैं, रिजर्व बैंक को यह उम्मीद भी है कि वित्त वर्ष के अंत में खरीफ की बेहतर फसल अर्थव्यवस्था को जरूर राहत देगी। सरकार प्रमुख सब्जियों व दूसरी चीजों की आपूर्ति बढ़ाने की बात कर रही है, जिसके सकारात्मक असर पड़ने की भी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल की स्थितियों में अगर केंद्रीय बैंक तीसरी और चौथी तिमाही के अपने महंगाई के अनुमानों को भी संशोधित करे, तो हैरत नहीं होगी।

ईरान को बुरे सपने आ रहे होंगे

अमेरिकियों ने हैरिस की आदर्शवादी नीतियों को नकार कर धमाकेदार ढंग से ट्रंप को अपना राष्ट्रपति चुना है, तो इसकी वजहें ट्रंप की शख्सियत की तरह स्पष्ट हैं। ट्रंप की नीतियों को लेकर बेशक बातें हो रही हैं, पर भारत के साथ उनके रिश्ते बेहतर ही बने रहेंगे। अलबत्ता ईरान को बुरे सपने जरूर आ रहे होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार (लगातार नहीं) जीत दर्ज कर डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास तो रच ही है, वह ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ऐसा करने वाले अमेरिका के पहले नेता भी बन गए हैं। तमाम कानूनी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने जिस महानतम ढंग से राजनीतिक वापसी की है, वैसा सदियों में शायद एक बार ही होता है। ट्रंप की धमाकेदार जीत (हालांकि मीडिया का एक वर्ग लगातार कह रहा था कि कांटे की टक्कर होगी) न केवल उनके एक राजनीतिज्ञ और नेता के रूप में, बल्कि विपक्षी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूरे अमेरिकी समाज के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। ट्रंप पर अस्थिरता, खराब आचरण, आक्रामक भाषा का प्रयोग और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन जैसे आरोप लगते रहे हैं, इसके बावजूद वह निस्संदेह एक करिश्माई नेता हैं, जिनके पास गहरा आत्मविश्वास, दृढ़ता और अपने समर्थकों को प्रेरित करने की गजब क्षमता है।

सुरेंद्र कुमार
पूर्व राजदूत

नवंबर, 2020 में मिली हार के बावजूद, उन्होंने यह कहना जारी रखा कि चुनाव में धांधली हुई थी और अदालती मामले उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश हैं। दो महाभियोग, 24 चोर आपराधिक मामलों के आरोप, सेक्स स्कैंडल, वर्गीकृत दस्तावेजों के अनधिकृत हस्तांतरण के आरोपों के बावजूद, ट्रंप झुके नहीं, उन्होंने तमाम बाधाओं का सामना करते हुए लड़ना जारी रखा और अंततः जीत हासिल की। इन सबसे उनकी लोकप्रियता और उनके कट्टर समर्थकों पर उनकी जादुई पकड़ कम नहीं हुई।

दक्षिण एशियाई देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे पास ऐसी महिला नेता रही हैं, जिन्होंने अपने देश का वर्षों तक नेतृत्व किया। पश्चिमी दुनिया में भी कई महिला नेताओं ने अपनी सरकारों की कमान संभाली है, लेकिन अमेरिका में नहीं। कमला हैरिस को दोहरी बाधा का सामना करना पड़ा : एक तो वह महिला हैं, दूसरा अश्वेत, एशियाई और कैरेबियाई मूल की हैं। दस सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस में कमला एकदम विजेता बनकर उभरीं। उन्होंने बिना आपा

खोए सभी जवाब बड़ी ही संजीदगी के साथ दिए और ट्रंप की तरह आप्रवासियों को कुत्ता-बिल्ली और जानवर खाने वाला बताने जैसी अप्रिय भाषा का इस्तेमाल भी नहीं किया। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने, विभाजनकारी मानसिकता को नकारने और बेहतर भविष्य के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने महिलाओं के गर्भपात अधिकार के लिए झंडा उठाया, अति धनाढ्यों पर कर लगाने तथा कम आमदनी वालों, मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायों और दैनिक वेतनभोगियों को मदद करने का वादा किया था। उन्होंने निश्चित क्षेत्रों की यूनियनों का समर्थन भी किया। लेकिन चुनाव परिणामों ने बता दिया कि उनकी आदर्शवादी बातें मतदाताओं को ज्यादा रास नहीं आईं। दूसरी ओर, ट्रंप के समर्थकों ने लोकतांत्रिक मानदंडों पर उनकी सभी गलतियां माफ कर दीं।

कमला की हार में योगदान देने वाले कई कारण रहे। कमला की हार का सबसे बड़ा कारण तो राष्ट्रपति बाइडन थे। वह वेमन से राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हुए और कमला का समर्थन तब किया, जब काफी देर हो चुकी थी। हैरिस को चुनाव अभियान के लिए करीब तीन महीने का समय मिला, जो एक तरह से समय के विपरीत दौड़ लगाना था। चालीस फीसदी रेटिंग के साथ बाइडन अलोकप्रिय राष्ट्रपति थे। बाइडन की सभी सत्ता विरोधी लहरों ने कमला के जहाज को डुबो दिया। जब उनसे पूछा गया कि वह बाइडन से अलग क्या करेंगी, तो कोई प्रभावी जवाब नहीं दे सकीं। यद्यपि वृहद स्तर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर कर रही है, महंगाई घटी है, बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन भवन निर्माण लागत और किराने की बढ़ती कीमतों ने जमीनी स्तर पर उनको नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर, ट्रंप द्वारा आप्रवासियों को दुष्कर्मी, अपराधी और स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनने वाला बताया गया, जिससे मतदाताओं के मन में आप्रवासियों को लेकर डर का माहौल निर्मित हुआ।

डेमोक्रेटिक पार्टी ने सामान्य कामेरे वर्ग की नब्ज पर अपनी पकड़ खो दी। ओपरा विन्फ्रे, लेडी गागा, बियॉन्सी, जेनिफर लोपेज और टेलर स्विफ्ट समेत अन्य हॉलीवुड हस्तियां भी इस वर्ग को प्रभावित नहीं कर सकीं और हैरिस के खिलाफ मतदान किया। जबकि श्वेत और अश्वेत, पुरुष मतदाताओं ने ट्रंप को करीब 54 फीसदी वोट दिए। हैरिस के लिए लातिन और भारतीय अमेरिकियों का समर्थन भी घट गया। इस्राइल-हमास-हिजबुल्ला-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से निपटने में नाकामी, विशेष रूप से गाजा में हजारों फलस्तीनियों की हत्या ने अरब अमेरिकियों को नाराज किया और उन्होंने हैरिस के विरोध में मतदान किया। हालांकि महिलाओं ने उन्हें वोट दिए, लेकिन महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर हैरिस का जोर बाजी पलटने वाला साबित नहीं हुआ।

सभी आयातों पर ट्रंप द्वारा दस से बीस फीसदी टैरिफ लगाने और आप्रवासियों के एच1बी वीजा पर सख्ती से भारत भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के अच्छे रिश्ते यहां काम आ सकते हैं। वहीं, पेरिस जलवायु समझौते से ट्रंप की संभावित वापसी एक झटका होगी। चीन के साथ उनका टैरिफ युद्ध चीन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बुरा होगा। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखते हुए रूस ने कुछ राहत की सांस ली होगी और उम्मीद है कि यूक्रेन के साथ युद्धविराम का रास्ता खुलेगा। लेकिन ट्रंप की इस्राइल समर्थक नीतियों को देखते हुए लेबनान और गाजा में युद्धविराम की संभावना कम दिखती है। लेकिन यह समझते हैं कि उनके द्वारा समर्थित अब्राहम समझौते (अरब-इस्राइल सामान्यीकरण) का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि वह पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त नहीं करा देते। अमेरिका प्रथम की नीति के तहत ट्रंप के आने से उब्ल्यूटीओ व नाटो को झटका लग सकता है, तो ईरानी नेतृत्व को बुरे सपने आ रहे होंगे। जीत के बाद दिए गए ट्रंप के भाषण वाले मंच पर एलन मस्क की मौजूदगी कॉरपोरेट जगत पर भी असर डाल सकती है। खैर देखना होगा कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के अपने बहुप्रचारित संदेश पर ट्रंप कितने खरे उतरते हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

वात्सकृष्ण भट्ट

बड़े से बड़े तूफान में जहाज लंगर के सहारे स्थिर और सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन में घोर विपदाओं को झेलता हुआ आशा के सहारे स्थिर और संतुलित बना रहता है।

आशा ही जिंदगी की ऑक्सीजन है

नैराश्य नामक बड़े भारी रोग की दवा है आशा। यदि वर्ष के भिन्न-भिन्न मौसमों की तरह मनुष्य के हृदय में भी तरह-तरह की दशाओं का दौरा हुआ करता है और उसमें भी ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर इत्यादि ऋतु एक-दूसरे के बाद आती हैं, तो यही कहना पड़ेगा कि निराशा के विकट शीतकाल की रात्रि के बाद ही आशा रूपी ऋतुराज के सूर्य का उदय होता है। हृदय यदि प्रमोद-उद्यान है, तो उसका पूरी तरह से सूखना आशा रूपी बसंत ऋतु में ही होता है। क्या ईश्वर की महिमा इसमें नहीं देखी जाती कि दुखी से दुखी जनों का सर्वस्व चले जाने पर भी आशा से उनका साथ नहीं छूटता। यदि मान और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है, जिसको उसके भक्त, धन के चले जाने पर भी अपनी गांठ में बांधे रहते हैं, तो सोचना चाहिए कि वह कितनी प्रिय वस्तु होगी, जो मनुष्य के हृदय को ढाढ़स और आराम देती है। आशा को यदि मनुष्य की जीवन रूपी नौका का लंगर, कहें तो ठीक होगा। क्योंकि जैसे बड़े से बड़े तूफान में जहाज लंगर के सहारे स्थिर और सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन में घोर विपदाओं को झेलता हुआ आशा के सहारे स्थिर और निश्चलमना बना रहता है।

मनुष्य के जीवन में कितना ही बड़े से बड़ा काम क्यों न हो, उसको करने की शक्ति का उद्भव इस आशा से ही होता है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन को बुद्धिमानों ने विविध भावनाओं के अभिनय की केवल रंगभूमि माना है। परदे के पीछे से धीरे-धीरे वह शब्द बातला देने वाला, जिससे हम चाहे जो पात्र बनें हों और चाहे जिस रस के नाटक का अभिनय अपने चरित्र द्वारा करते हों, उसमें दृढ़तापूर्वक लगे रहते हैं। संसार को भिन्न-भिन्न कलह की रणभूमि मानें, तो उस अपरिहार्य रणभूमि में घायलों के घाव पर रखा जाने वाला मरहम आशा ही है। जिस किसी ने संसार में आकर किसी बात का यत्न न किया हो और किसी वस्तु की खोज में अपने को न डाल दिया हो, उससे बढ़कर व्यर्थ और नीरस जीवन किसका होगा? जब यह बात है, तो बतलाइए किसी प्रकार के प्रयत्नमात्र की जान आशा को छोड़ किसी दूसरे को कह सकते हैं? क्योंकि कैसे संभव है कि मनुष्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के प्रयत्न में लगा हो और आशा से उसका हृदय शून्य हो?

किसी काम के अभिलषित परिणाम में अमृत का गुण भर देना, यह शक्ति सिवाय आशा के और किसमें है। संसार में जो कुछ भलाई हुई है या होगी, उस सब का मूल सदा प्रयत्न है और इस प्रयत्न की जान आशा है। यदि आशा केवल मृगतृष्णा ही है, तब भी वह नाउम्मीदी से अच्छी है। इस आशारूपी प्रबल वायु से हृदय रूपी सागर में जो दूर तक तरंगें उठती हैं, उन तरंगों की अवधि नजर में नहीं आ सकती। संसारमात्र इस आशा की रस्सी से कस हुआ है। आशा ही एक हमारा ऐसा सच्चा साथी है, जो लड़कपन से अंतकाल तक साथ देता है और आशा ही द्वारा उत्पन्न वे भाव हैं, जो हमें मरने के बाद की दशा के बारे में भी सोचने को मजबूर करते हैं। इस संसार में अपनी और दूसरे की भलाई का परम आधार आशा ही है।

नकारात्मक न बनें

सूत्र

हमारा जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। जीवन में उतार-चढ़ाव भी आते रहेंगे, लेकिन कभी भी नकारात्मक न बनें। जब जीवन-मरण की स्थिति आ जाती है, तो अस्पताल में मरीज को ऑक्सीजन के सहारे रखा जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन की सभी समस्याओं को हल करने की ऑक्सीजन आशा ही है।

दूसरा पहलू

ताइवान में 13 साल तक 4,80,000 लोगों पर हुए अध्ययन के मुताबिक, ज्यादा समय तक बैठने से उम्र घटती है।

लंबे समय तक बैठना यानी जल्दी बुढ़ापा

हम सबने यह सुना है कि लंबे समय तक बैठे रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। कुर्सी पर लंबे समय तक बैठे रहने से शारीरिक अभ्यास से मिलने वाले लाभ बेअसर हो जाते हैं। यही नहीं, बैठे रहने का समय लंबे समय तक चला, तो उम्र घट सकती है। लेकिन यह हकीकत है कि दुनिया भर में कुर्सियों पर बैठे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिकी पुरुष औसतन साढ़े नौ घंटे कुर्सियों पर बैठते हैं। महिलाओं के बैठने के घंटे पुरुषों से कम हैं, लेकिन सभी लोग इससे सहमत हैं कि पहले की पीढ़ी की तुलना में आज की पीढ़ी के लोग ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं। इसके नतीजे भीषण हो सकते हैं।

जेन मर्फी

ताइवान में एक एजेंसी ने 13 साल तक 4,80,000 लोगों का सर्वे करने के बाद पाया कि जो लोग ऑफिस में हमेशा बैठे रहते हैं, उनके दिल की बीमारी से मरे जाने की आशंका न बैठने वालों की तुलना में 34 प्रतिशत ज्यादा होती है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इस खतरे से बचने का एक तरीका यही है कि रोज की कसरत में 15 मिनट से आधे घंटे की अवधि बढ़ा दी जाए। अगर बैठने की अवधि के अनुपात में कसरत करने या टहलने की अवधि बढ़ाई जाए, तो बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। अगर ऐसा संभव न हो, तो थोड़ी-थोड़ी अवधि में कुर्सी से उठकर टहलना भी लाभदायक होगा।

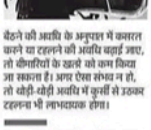

बैठने की अवधि के अनुपात में कसरत करने या टहलने की अवधि बढ़ाई जाए, तो बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। अगर ऐसा संभव न हो, तो थोड़ी-थोड़ी अवधि में कुर्सी से उठकर टहलना भी लाभदायक होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बैठे रहना हमारे दिल, जोड़ों, मांसपेशियों, चयापचय और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि लगातार बैठे रहने वाले व्यक्ति अगर नियमित रूप से कसरत करते हों, तब भी उनमें दिल की बीमारी होने या दिल के दौरे पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। एसोसिएशन का मानना है कि लगातार दस घंटे तक कुर्सी पर बैठना खतरे को आमंत्रित करने जैसा है। इससे कमर दर्द होने की आशंका भी रहती है। ज्यादा देर तक बैठे रहने से कैलोरी भी कम खर्च होती है। यह जीवनशैली लंबे समय तक रही, तो ब्लड शुगर बढ़ने के साथ मोटापा बढ़ने का भी खतरा पैदा होता है। अगर अमेरिका की ही बात करें, तो जीवनशैली में आए बदलाव के कारण अमेरिकी लोग 50 साल पहले की तुलना में 100 कैलोरी कम खर्च कर पा रहे हैं। जबकि आधे घंटे टहलने पर ही इतनी कैलोरी खर्च हो सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने से तनाव और दुश्चिंता भी बढ़ती है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

अमेरिका से व्यापार

भारत और अमेरिका के बीच बीते एक दशक में व्यापार में 1868.3 करोड़ डॉलर यानी दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

	व्यापार के आंकड़े करोड़ डॉलर में
2013-14	1663.7
2017-18	2126.7
2020-21	2273.5
2021-22	3285.3
2023-24	3532.0

स्रोत : MoCAI

भक्तिसार ने अपनी लिखी हुई पुस्तकों को नदी में प्रवाहित कर दिया, लेकिन उनमें से दो पुस्तकें नहीं बहीं-जिनका सार है, 'मुक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है'।

नारायण ही सब कुछ हैं

दक्षिण में तिरुमड़िरी (महीसरपुर) नाम का प्रसिद्ध तीर्थ है, वहां पर भक्तिसार नाम के बड़े संत हुए। बताया जाता है कि बचपन में उनके माता-पिता ने उनको वन में छोड़ दिया था। तिरुवाड़न नाम का व्याध और उसकी पत्नी वन में गए थे। वहां उनकी दृष्टि एक बालक पर पड़ी। उन्होंने उसे भगवान की देन समझकर उठा लिया और अपने घर ले आए। उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस बालक को अपने बालक के रूप में पाला-पोसा और उसका नाम भक्तिसार रखा। भक्तिसार को देखकर एक वृद्ध ने कहा कि यह बालक असाधारण है।

भक्तिसार अलौकिक व्यक्ति थे, उन्होंने कम उम्र में लगभग सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए थे। वह भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते थे कि हे प्रभु! मुझे जन्म-मरण के चक्कर से छुड़ा दो। एक बार वह सरोवर के तट पर ध्यान लगा रहे थे, तभी एक देवता आए और भक्तिसार से कहा कि वर मांग लो।

अंतर्यात्रा
संकलित

भक्तिसार ने उनसे पूछा-क्या आप मुझे मुक्ति दे सकते हो? क्या आप किसी की मृत्यु टाल सकते हो? देवता ने कहा नहीं। भक्तिसार ने उनसे कहा, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्तिसार ने कई पुस्तकें लिखी थीं, जो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दीं। लेकिन उनमें से दो पुस्तकें वही नहीं। उन पुस्तकों का सार है, 'मुक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है'। नारायण हो जाता, ज्ञेय और ज्ञान, तीनों हैं। नारायण ही सब कुछ हैं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 15 अप्रैल,1962

डॉ. राधाकृष्णन राष्ट्रपति और डॉ. हुसैन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार

डॉ. जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति

कांग्रेस कार्यसमिति ने भारत के नए राष्ट्रपति पद के लिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति पद के लिए डॉ. जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और दोनों के नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए हैं।

बैंकिंग में एआई की सीमाएं हैं

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रामाणिकता आंकड़ों की विश्वसनीयता पर ही निर्भर है। इससे प्राप्त विश्लेषण अविश्वसनीय और पक्षपाती भी हो सकते हैं।

पीएस वोहरा — तकनीकी

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। समाज में इसकी उपयोगिता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसी कारण आमजन में इसकी समझ का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। हाल-फिलहाल तो इसका अधिक उपयोग वीडियो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग और कुछ हद तक चैटजीपीटी के माध्यम से व्यक्तिगत क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बड़े व्यापारों और औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न तरह की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त लेने के लिए भी एआई के माध्यम से निर्मित आर्थिक विश्लेषणों को ज्यादा तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है। इसलिए चर्चा हो रही है कि एआई द्वारा निर्मित विभिन्न विश्लेषण और मूल्यांकन कितने उपयोगी हैं और इन पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है?

इस मुद्दे पर एकाएक ध्यान तब गया, जब बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को चेताया कि एआई पर अधिक

निर्भरता कुछ नए जोखिमों को पैदा कर सकती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की में रुकावट भी बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष अब तक तकरीबन 58 प्रतिशत बैंकों में एआई को विभिन्न निर्णयों में शामिल किया जा चुका है और यह संख्या आगे बढ़कर 77 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। यानी लगभग पूरी बैंकिंग व्यवस्था आने वाले एक या दो वर्षों में एआई विश्लेषण व मूल्यांकन पर निर्भर हो सकती है। एआई पर बैंकों की बढ़ती निर्भरता के पीछे उनके कुछ व्यावसायिक उद्देश्य भी हैं। एआई के माध्यम से बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थान यह जान सकते हैं कि समाज में अब भी कौन-कौन बैंकिंग व्यवस्था के वास्तविक उपयोग से दूर हैं। बैंकिंग व्यवस्था एआई की मदद से विभिन्न पिछड़े परिवारों घरेल महिलाओं, छोटे किसानों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए अलग-अलग वित्तीय योजनाएं बनाकर उन्हें खुद से जोड़ सकती है। इससे बैंकिंग व्यवस्था का लाभ समाज के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। यह देश में गरीबी उन्मूलन के लिए एक सहारा भी बन सकता है। दूसरा पक्ष यह भी है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था की लाभदायकता में भी बढ़ोतरी होगी।

एआई का बैंकिंग में एक अन्य अच्छा उपयोग व्यक्तियों की अप्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन है। इसके अंतर्गत पुरुष व महिलाओं के विभिन्न प्रकार के वित्तीय व्यवहारों का आकलन होता है। इससे किसी उत्पाद अथवा ब्रांड के प्रति व्यक्ति की सोच का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके बाद व्यक्ति की वित्तीय क्षमता का विश्लेषण करना बैंकों के लिए आगामी स्तर होता है। आखिर में उसे प्रत्यक्ष तौर पर विभिन्न वित्तीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को खरीदने व उपयोग में लाना है, ताकि लाभदायकता बढ़े। एक अन्य मुख्य उद्देश्य एआई के उपयोग से विभिन्न तरह के व्यावसायिक गबन और धोखे को रोकना है। इसकी चपेट में आज भारतीय समाज है और इससे बैंकिंग व्यवस्था भी चिंतित है। अमेरिका में वर्ष 2023 में तकरीबन 13 अरब डॉलर के वित्तीय गबन को इस तकनीक से रोका जा सका। इससे स्पष्ट है कि एआई के माध्यम से साइबर घोटालों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। इन सबके बावजूद तथ्य है कि एआई एक तकनीक मात्र ही है और इसकी विश्वसनीयता इसके द्वारा उपयोग में लिए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता पर ही निर्भर है। इस सीमा के चलते एआई से प्राप्त विश्लेषण अविश्वसनीय, अनुपयोगी और पक्षपाती भी हो सकते हैं।

कुछ वर्षों पूर्व विश्व की एक बड़ी ऑनलाइन कंपनी ने अपने यहां कर्मचारियों की भर्ती करते समय उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से जब एआई की रिपोर्ट का विश्लेषण किया, तो यह पाया गया कि उसमें किसी भी महिला आवेदक को जगह ही नहीं मिली। यह विश्लेषण अचंभित करने वाला था। गहन जांच में पता चला कि बीते कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा चुने गए पुरुष श्रमिकों का ही आंकड़ा एआई को उपलब्ध करवाया गया था, जिसके कारण नए चयन के समय में सभी आवेदकों के विश्लेषण में एआई द्वारा केवल पुरुष श्रमिकों के आवेदनों को ही प्राथमिकता दी गई।

वित्तीय क्षेत्र में भी एआई की कुछ सीमाएं हैं, जैसे व्यक्तियों की वित्तीय साख या क्रेडिट स्कोर के निर्धारण में सभी संस्थाओं द्वारा एक ही तरह के विश्लेषण और मूल्यांकन किए जाते हैं। एआई के उपयोग की सीमाओं को इस तरह भी समझें कि त्योहारों के मौसम में अमूमन सब बढ़-चढ़कर खरीदारी करते हैं। अब अगर किसी दीपावली में खरीदारी कम हुई और बीते वर्षों में खूब खरीदारी हुई थी, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एआई के विश्लेषण से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी कि देश मंदी की तरफ अग्रसर है, जबकि मंदी की वास्तविक परिभाषा लगातार तीन तिमाहियों में नकारात्मक जीडीपी के रहने पर आधारित होती है।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • बृहस्पतिवार • 14 नवम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कुशल पुरुष की वाणी प्रतिकूल बोलने वाले प्रबुद्ध वक्ताओं को मूक बना देती है, और पक्ष में बोलने वाले मंदमति को निपुण।

-माघ

ट्रंप का भारत प्रेम

अमेरिका में राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम का गठन करना शुरू कर दिया है। अभी तक जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उससे जाहिर होता है कि अमेरिका की घरेलू और विदेश नीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलान मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करेंगे। यह नया विभाग है जिसे ट्रंप ने 'सेव अमेरिका' अभियान के लिए जरूरी बताया है। ट्रंप के मुताबिक, यह विभाग नौकरशाही, अतिरिक्त नियम-कानून को खत्म करने, अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेगा। विवेक परंपरावादी और शाकाहारी हिन्दू हैं। उन्होंने अमेरिका की वर्तमान विभाजनकारी राजनीति और अंतरिक संघर्ष से उबरने के

लिए 10 सूत्री गुरूमंत्र दिया था। उनका मानना है कि नौकरशाही के दबदबे के लिए कोई स्थान नहीं है और संघीय जांच एजेंसी एफबीआई को भंग करने की बात कही थी। विवेक रामास्वामी को ट्रंप ने देशभक्त अमेरिकी बताया है। फ्लोरिडा के भारत समर्थक सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रूबियो की छवि भारत समर्थक और चीन-विरोधी है। वे चीन के सामान पर टैक्स बढ़ाए जाने की मांग कर चुके हैं। मांग स्वीकार कर ली जाती है तो चीन के खिलाफ बड़ा रणनीतिक कदम होगा और जिसका अमेरिका सहित यूरोपीय देशों पर विपरीत असर पड़ेगा। रूबियो ने इस साल सीनेट में एक विधेयक पेश किया था जिसका मजमून भारत-अमेरिकी संबंध मजबूत करना और आतंकवाद के प्रसार के कारण पाकिस्तान को सुरक्षा मदद रोकना था। भारत समर्थक और चीन विरोधी रुख रखने वाले फ्लोरिडा के सांसद माइक वॉल्टज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह इंडिया कॉक्स समूह से जुड़े हैं जो भारत-अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की वकालत करता है। ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल और भारत समर्थक लोगों को शामिल किए जाने से जाहिर होता है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। लेकिन ट्रंप चीन के प्रति क्या रुख अपनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। वह चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं और विदेश मंत्री बनाए गए मार्को रूबियो सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन अशांति फैलाने का दोषी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन चीन के प्रति सख्त रवैया अपना सकता है।

सख्त तेवर

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ठोस सुधार को लेकर चल रहे टाल-मटोल पर सख्त तेवर दिखाए हैं। कहा है कि इससे स्थाई सदस्यता में विस्तार और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कम प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने जैसे महत्त्वपूर्ण तत्व अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जा सकते हैं। भारत ने कहा है कि 1965 के बाद से हमारे पास दिखाने के लिए कोई परिणाम नहीं है। 1965 में परिषद की सदस्यता छह निर्वाचित सदस्यों से बढ़ा कर दस कर दी गई थी। भारत ने जोर दिया कि अंतर सरकारी वार्ता में वास्तविक ठोस प्रगति चाहता है। भारत ने यथास्थिति का पक्ष लेने वाले देशों द्वारा आम सहमति का तर्क दिए जाने पर चिंता भी जताई। ग्लोबल साउथ के सदस्य के रूप में भारत का मानना है कि प्रतिनिधित्व न केवल परिषद, बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र की वैधता और प्रभावशीलता दोनों के लिए अपरिहार्य शर्त है। ग्लोबल साउथ का अर्थ आर्थिक रूप से कम विकसित

देशों के लिए लगाया जाता है। सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य देश होते हैं, जिनमें से बस पांच स्थाई होते हैं। इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भावना से की गई थी। आठ बार अस्थाई सदस्य चुने जाने के बावजूद भारत लंबे अरसे से स्थायी सदस्यता का अब तक प्रबल दावेदार ही है। हालांकि चीन इसका मुखर विरोधी है परंतु भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। परमाणु हथियार संपन्न देश-दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था होने के चलते मौजूदा स्थायी सदस्यों के मुकाबले तनिक पीछे नहीं रहा। इसलिए उसकी नाराजगी की अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत के पक्ष में जाने वाली बात है कि ब्रिटेन हमारे साथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान और ब्राजील को भी स्थायी प्रतिनिधित्व देने का पक्षधर है। हालांकि दुनिया के तमाम देश सदस्यता पाने का आवेदन करते रहते हैं। मगर भारत ने विश्व पटल पर जिस तरह अपनी स्थिति लगातार मजबूत की है, उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि उसके तेवर बिला-वजह नहीं हैं। वह जिस ठोस प्रगति की बात उठा रहा है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र की वैधता और उसके प्रभाव को चुनौती देते हुए भारत ने न केवल दृढ़तापूर्वक अपनी दावेदारी को दोहराया है, बल्कि दुनिया के समक्ष अपनी अहमियत जताने में भी हिचक नहीं रहा।

कटाक्ष/ सहीराम

फायदा-नुकसान

चुनाव का एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है जी कि रसोई गैस एकदम सस्ती होने लगती है। हजार-बारह सौ का गैस सिलिंडर एकदम चार-पांच सौ पर आ जाता है। सचमुच आ जाता है, यह तो नहीं कहा जा सकता, पर ऐसा वादा जरूर हो जाता है। गुड़ चाहे न मिले, पर गुड़ की सी बात हो जाती है। यह ऐसा फायदा है साहब कि इस पर एक देश, एक चुनाव का सपना सौ बार कुर्बान हो सकता है। वैसे यह भी हो सकता है कि इसे लागू करने पर जोर भी इसीलिए दिया जा रहा हो कि सरकार को रसोई गैस की कीमत बार-बार न घटानी पड़े। अब तो जहां कहीं भी चुनाव होता है, वहां सबसे पहले रसोई गैस की कीमत घटाने का वादा होता है। नौकरी देने का वादा नहीं होता। एक जमाना था जब बिजली, सड़क, पानी का वादा किया जाता था। अब वे सारे वादे घट कर रसोई गैस के सिलिंडर में समा गए हैं। लेकिन भारत की विविधता के दर्शन यहां भी हो जाते हैं। एक राज्य में अगर सिलिंडर की कीमत घटा कर पांच सौ की जाती है, तो दूसरे में घटा कर साढ़े पांच सौ की जाती है। यही हाल पार्टियों का भी है-एक घटा कर पांच सौ करती है, तो दूसरी घटा कर छः सौ करती है। चुनाव आने का अगर यह सबसे बड़ा फायदा होता है तो जी एक सबसे बड़ा नुकसान भी होता है। बल्कि फायदा एक होता है और नुकसान कई हो जाते हैं। एक तो देश ही टूटने लगता है। देश के टूटने का डर इतना सताने लगता है कि लोग पुलों के टूटने, रेलों-पटरियों के टूटने को भूल जाते हैं। यहां तक कि नौजवान अपने टूटते सपनों को भी भूल जाते हैं, और देश टूटने की चिंता करने लगते हैं। वैसे चुनावों तक देश सुरक्षित रहता है। एक और नुकसान यह होता है कि चीजें गायब होनी शुरू हो जाती हैं। नहीं सचमुच तो गायब नहीं होतीं, पर उनके गायब होने का डर पैदा हो जाता है। जैसे दो भैंसें हैं तो एक के गायब होने का डर पैदा हो जाता है। मंगलसूत्र गायब होने का डर पैदा हो जाता है। जमीन छीनने का डर पैदा होने लगता है। बल्कि यह गायब होने से ज्यादा छीने जाने का डर होता है। इधर तो बेटी छीनने का ही डर पैदा हो गया। ऐसी छीन-झपट क्यों मचती है। यार कोई सरकार, कोई कायदा-कानून भी है कि नहीं। लोग कहते हैं कि यह होती तो वोटों की ही छीन-झपट है, वस नाम भैंस का, मंगलसूत्र का और जमीन-जायदाद का हो जाता है।

मकड़जाल में फंसते बच्चे

तकनीक और आधुनिकता

राजेश मणि

वर्तमान युग में भारतीय समाज त्वरित गति से तकनीकी और सामाजिक बदलावों का सामना कर रहा है। तकनीकी विकास ने हमारे बच्चों के जीवन को जहां नये अवसर दिए हैं, वहीं कई संकटों को भी जन्म दिया है। आज के बच्चे, जो हर रोज स्मार्टफोन, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं, अपनी मानसिकता, आदतों और जीवनशैली में तेजी से बदलाव महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत में इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक, सब कुछ डिजिटल हो गया है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल गेमिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वीडियोग्राफी जैसे अत्याधुनिक साधन बच्चों की सोच, आदतों और जीवनशैली को आकार दे रहे हैं। बच्चों का अधिकांश समय स्मार्टफोन, टैबलेट, और कंप्यूटर पर बीतता है। परिणामस्वरूप बच्चों में शारीरिक गतिविधियों की कमी हो रही है। शारीरिक निष्क्रियता से मोटापा, हड्डियों की कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं। लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से उनकी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और आंखों की रोशनी में भी गिरावट आ रही है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों को साइबरबुलिंग, पोर्नोग्राफी, और असामाजिक सामग्री का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके मानसिक विकास को नुकसान पहुंचाता है। सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने का दबाव भी बच्चों को तनाव और असंतोष की ओर धकेल रहा है।

तकनीकी विकास ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल उपकरणों का बढ़ता उपयोग बच्चों को नई पद्धतियों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे रहा है। इंटरनेट ने जहां बच्चों को दुनिया भर की जानकारी से परिचित कराया है, वहीं वह पारंपरिक शिक्षा की आदतों और मूल्यों से भी उन्हें दूर कर रहा है। बच्चों को खुद से पढ़ाई करने और स्वाध्याय की आदत डालने की बजाय वे अब इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों पर निर्भर हो गए हैं। साथ ही, शिक्षा में नैतिक और सामाजिक शिक्षा की कमी भी महसूस हो रही है। आजकल के बच्चे भले ही तकनीकी दृष्टि से बेहद प्रगति कर गए हैं, लेकिन उनके भीतर मानवीय मूल्यों, नैतिक शिक्षा और पारिवारिक संबंधों की अहमियत धीरे-धीरे कम हो रही है। यह स्थिति बच्चों को मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर बना रही है। भारत में पारंपरिक रूप से बच्चों से उच्च शिक्षा की उम्मीदें बहुत अधिक होती हैं। माता-पिता और समाज बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे

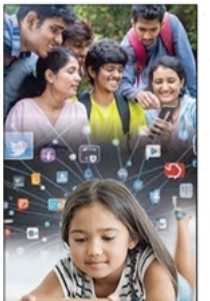

हमेशा सर्वोत्तम परिणाम देंगे, जो मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। बच्चों को अपनी पहचान बनाने में भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि वे समाज के मानकों में बंध कर जीने की कोशिश करते हैं। यह दबाव न उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी डगमगा सकता है।

इसके अलावा, आजकल परिवारों में माता-पिता की व्यस्त जीवनशैली के कारण बच्चों को पर्याप्त समय और ध्यान नहीं मिल पाता। परिणाम यह होता है कि बच्चे अपने माता-पिता से मानसिक और भावनात्मक सहायता प्राप्त नहीं कर पाते और इस स्थिति में उनका मानसिक विकास बाधित हो सकता है।

इस संकट से उबरने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाने होंगे-संतुलित जीवनशैली: बच्चों को तकनीकी उपकरणों का उपयोग सीमित करना चाहिए। शारीरिक गतिविधियों, खेलकूद और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलना चाहिए। संतुलित जीवनशैली बच्चों को मानसिक-शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा: बच्चों को तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और मानवता के मूल्यों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे बच्चों का मानसिक-सामाजिक विकास संतुलित रूप से हो सकता है। पारिवारिक समर्थन: बच्चों को अपने परिवार से मानसिक-भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। माता-पिता को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें समझने और उनकी समस्याओं का हल निकालने में मदद करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल: बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चे किसी प्रकार के मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहे हैं, तो उन्हें काउंसलिंग और उचित मानसिक उपचार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। शिक्षा में सुधार: पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। बच्चों को आधुनिक ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए।

सरकार भी अपने तरीकों से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है भारत सरकार, प्रदेश सरकारें समय- समय पर जागरूकता अभियान और दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा पर किशोरों/छात्रों के लिए पुस्तिका भी बनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाइल्ड पोर्न देखना या उसे स्टोर करके रखना भी पास्को और आईटी कानून के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पास्को एक्ट की धारा 15 के अनुसार चाइल्ड पोर्न देखना, रखना, प्रकाशित करना या उसे प्रसारित करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिया। कहा कि अदालतों को अपने फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव मैटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए।

सही मायने में 'बाल दिवस' का स्वरूप तब दिखेगा जब हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलें। बच्चों के प्रति कोई हिंसा न हो। बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण, बाल विवाह इस सभी चीजों से आजादी हो। भारत में आज के बच्चे तकनीकी विकास और आधुनिकता के प्रभाव से जूझ रहे हैं। यह तकनीकी युग उनके लिए कई नये अवसर उत्पन्न करता है, लेकिन इसके साथ ही यह उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है। इस संकट से उबरने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें बच्चों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(लेखक मानव सेवा संस्थान 'सेवा' में निदेशक हैं, व्यक्त विचार निजी हैं)

सही मायने में 'बाल दिवस' का स्वरूप तब दिखेगा जब हम प्रधानमंत्री मोदी के सपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलें। बच्चों के प्रति कोई हिंसा न हो। आज बच्चे तकनीकी विकास और आधुनिकता के प्रभाव से जूझ रहे हैं। तकनीकी युग उनके लिए नये अवसर उत्पन्न करता है, लेकिन साथ ही उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है। इस संकट से उबरने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है

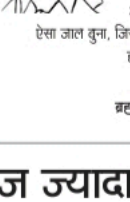

कमला हैरिस की हार में यही सबक छिपा है कि जब मीडिया हद से ज्यादा पक्षपाती होकर एक पार्टी के साथ जुड़ जाए तो वह उस पार्टी को ही छलने का काम करता है। अमेरिकी मीडिया ने फंतासी भरा ऐसा जाल बुना, जिसका स्वाभाविक तौर पर जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं था।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

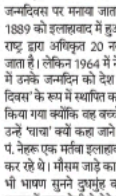

बाल दिवस **डॉ. रमेश ठाकुर**

नेहरू जैसे 'चाचा' आज ज्यादा जरूरी

आज खास दिन 'बाल दिवस' है, और चाचा नेहरू हमारा परिचित ही है। पर लोग नहीं जानते कि नेहरू जी आखिर क्यों के 'चाचा' कैसे कहलाए? अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ हैं। वैसे, 'बाल दिवस' आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म 14 नवम्बर, 1889 को इलाहाबाद में हुआ था जबकि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत 20 नवम्बर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद संसद में उनके जन्मदिन को देश में आधिकारिक तौर पर 'बाल दिवस' के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव एकमत से पारित किया गया क्योंकि वह बच्चों को नितांत प्रिय थे। उन्हें 'चाचा' क्यों कहा जाने लगा, यह दिलचस्प वाक्या है। पं. नेहरू एक मर्तबा इलाहाबाद में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मौसम जाड़े का था। सभा में एक बुजुर्ग महिला भी भाषण सुनने दुधमुंह बच्चे के साथ पहुंची थी। जारी भाषण में बच्चा तेजी से रोने लगा। पं. नेहरू की जैसे ही नजर बच्चे के रोने पर पड़ी, तो उन्होंने भाषण रुकवा दिया और तुरंत अपने अंगरक्षक को बच्चा और उसकी मां को मंच पर लाने को कहा। मां अपने बच्चे के साथ जैसे ही मंच पर चढ़ी, नेहरू ने अपने बहकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा पंडित जी की गोद में जाते ही चुप हो गया और उनकी जेब में लगे पेन से खेलने लगा। बच्चे के प्रति नेहरू के प्यार-स्नेह को देख कर सभा में उपस्थित लोग अचंभित हो गए और उसी समय से लोगों ने उन्हें 'चाचा' कहना शुरू कर दिया। हालांकि बच्चे से प्यार तो हर कोई करता है लेकिन नेहरू का प्यार वेशकीमती, अद्भुत, चमत्कारी होता था। रोते हुए बच्चे भी उनके सान्निध्य जाकर एकाएक चुप हो जाते थे। बच्चों को चुप कराने की उनके पास पता नहीं कौन सी अद्भुत कला थी, जो सभी को आश्चर्यचकित करती थी। नेहरू बच्चों के अधिकारों और एक शिक्षा प्रणाली के पक्षधर और समर्थक थे। प्रत्येक बच्चे को देश का भविष्य कहते थे। फूलपुर की चुनावी सभा में नेहरू ने एक बार कहा था कि बच्चे बगीचे में कलियों की तरह होते हैं। उनका प्यार से पालन-पोषण करना चाहिए क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं।

मौजूदा वक्त में जिस बेहिसाब से समूचे देश के नौनिहालों

के प्रति अत्याचार, विभिन्न किस्म की समस्याएं और अपराध बढ़े हैं, वो अगर जिंदा होते तो बहुत दुखी होते। एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट बच्चों के गायब होने के जो आंकड़े प्रस्तुत करती है, वो निश्चित ही डरावने हैं। तमाम हुकूमती कोशिशों के बावजूद बाल समस्याएं रुकने का नाम नहीं लेतीं। बाल दिवस के मौके पर आज देश भर के स्कूलों में गायन, निबंध, वाद-विवाद, खेलकूद जैसी तमाम प्रतियोगिताएं होंगी। अधिकांश जगहों पर नेहरू की जीवनी पर लेख-लेखन कंपटीशन आयोजित होंगे। नेहरू बच्चों को राष्ट्र की संपत्ति मानते थे। अक्सर नौनिहालों को मुल्क के सबसे कीमती संसाधन के रूप में संदर्भित करते थे। इसलिए अपने युवा नागरिकों के जीवन की बेहतरी के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के जरिए बच्चों में खुशियां, उनके अधिकारों और उनके उज्ज्वल भविष्य को संवारने के लिए जागरूकता भी फैलाई जाती है। बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित, खुशहाल और शिक्षा से भरपूर जीवन देने के लिए सभी को संकल्पित होना चाहिए। 1954 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 20 नवम्बर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया गया था।

पर भारत ने इस दिवस को 14 नवम्बर यानी पं. नेहरू के जन्मदिन पर मनाने का निर्णय लिया। यह दिन बाल अधिकारों की रक्षा करने, सुरक्षित वातावरण देने और उनकी शिक्षा-स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर केंद्रित होता है। बच्चों के प्रति बढ़ते अत्याचार, बाल श्रम और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं पर जागरूकता निरंतर फैलती रहनी चाहिए। बच्चों को बचपन में सही मार्गदर्शन और प्यार मिलना चाहिए। सभी बच्चे बिना भेदभाव स्वतंत्र रूप से सीखने और बढ़ने का अधिकार रखते हैं। पं. नेहरू हमेशा बच्चों के बीच जाकर उनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। उनका मानना था कि बच्चों में मासूमियत, सच्चाई, और निष्ठा होती है, जो बड़ों को भी प्रेरणा देती हैं। शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम से सुरक्षा और सुरक्षित व प्यार भरे वातावरण में बढ़ने का अधिकार हम सभी को मिल कर दिलवाना चाहिए। हालांकि, भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाल संरक्षण कानून और विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। इनका आम जन को भी मिल कर सहयोग करना चाहिए।

(लेखक बाल संरक्षण कार्यकर्ता और केंद्र की बाल कल्याण समिति निपसिड के सदस्य हैं)

उपासना **श्री राम शर्मा आचार्य**

हमारा भगवान भी उसी तरह का है। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी करना भगवान के लिए करना, समाज के लिए करना। हमने सारी

जिंदगी इसी तरह का काम किया है और जितना किया है, उतना पा लिया है। आगे जो हम करेंगे, उसके एवज में भी हम पाते रहेंगे। आपका तो हमेशा दिल धड़कता रहता है। आपको तो भगवान का नाम लेना सहज मालूम पड़ता है, पर भगवान का काम करना मुश्किल पड़ता है तथा उसके लिए पैसा लगाना तो और भी मुश्किल मालूम पड़ता है। यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, परंतु हमारे लिए तो एकदम सरल है। हमारे दिमाग, शरीर, साहित्य, प्लानिंग को देख लीजिए, ये हमारी सिद्धियां हैं। ये सारी हमारी प्रत्यक्ष सिद्धियां हैं। सिद्धियां तो हमारी दिखलाई नहीं पड़तीं। हमें खूब आराम से नींद आ जाती है, पास में नगाड़ा भी बजता रहे, तो भी कोई परवाह नहीं। चिंता हमारे पास नहीं है। हम निर्भीक हैं। आत्म संतोष हमारी सिद्धि है। हमारा लोक सम्मान बहुत है। लोक सम्मान उसे कहते हैं-जिसमें जनता का सहयोग मिलता है। भगवान का अनुग्रह भी हमें मिला है। अनुग्रह कैसा होता है, कहते हैं कि देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं। हमारे ऊपर हमेशा फूल बरसते रहते हैं, जिन्हें हम प्रोत्साहन, साहस, हिम्मत, प्रेरणा, उत्साह, उम्मीद कह सकते हैं। गिन्नी, हम अपने पिता के बफादार बेटे हैं। हमने उनके धन को पाया है, क्योंकि उनके नाम को वदनाम नहीं किया है। अपने पिता के व्यवसाय को जिंदा रखा है। उनके बगीचे को हमेशा हरा-भरा तथा अच्छा बनाने का प्रयास किया है। मनुष्यों को सुसंस्कारी तथा समुन्नत बनाने के लिए जो भी संभव था, उसे हमने पूरा किया है। हमारे पिता हमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। युवराज वह होता है, जो अपने पिता के समान हो जाता है। हम अपने पिता के युवराज हैं। हम अपने पिता के समकक्ष हो गए हैं। हमने पिता को गुम्बज की आवाज-प्रतिध्वनि के रूप में देखा है। जो शब्द हमने कहा-वैसा ही सुनने को मिला। हमने कहा कि जो कुछ भी हमारे पास है, वह आपका है। उसने भी ऐसा ही कहा कि जो कुछ हमारे पास है, वह तुम्हारा है। हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका, उसने भी वैसा ही कहा।

रीडर्स मेल

खर्चीले विवाह समारोह क्यों

भारतीय समाज में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। साधन-संपन्न लोगों द्वारा जिन प्रवृत्तियों को अपनाया जाता है, उनकी देखा-देखी अपनी हैसियत के अनुसार मध्यम एवं निम्न वर्ग करता है। विवाह जैसे मंगल प्रसंग को भी श्रेष्ठी वर्ग द्वारा दिखावे और ईगो प्रदर्शन का माध्यम बना दिया गया है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में विवाह समारोहों में खर्च करने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

ललित महालकरी, इंदौर

पार्टी नहीं अपना प्रतिनिधि चुनें

अब लोग पूछते हैं कि चुनाव की दिशा किस ओर है? हमारा नेता कौन होगा? हमारा प्रतिनिधि कैसा होगा? हम अपने प्रतिनिधि के चुनाव के समय सोचते हैं कि वह किस पार्टी से है। क्या यह सोच सही है? किसी पार्टी से संबंध न रखने वाले व्यक्ति की विचारधारा भी समाज के विकास के लिए तर्कपूर्ण हो सकती है। इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि कौन हो, के स्थान पर सोचना होगा कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो? हमें पार्टी प्रतिनिधि की दृष्टि को छोड़ कर समाज के विकास के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने का अवसर मिला है। इस अवसर को ध्यान में रख कर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। पार्टी प्रतिनिधि नहीं, बल्कि जन कल्याण, समाज कल्याण, राज्य कल्याण और देश कल्याण के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

अमेरिका में पुरुष प्रधानता

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमाकेदार वापसी करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सभी राजनीतिक विश्लेषक कांटे की टक्कर बता रहे थे, लेकिन परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि चुनाव एकतरफा रहा। आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई भी महिला राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत सकी है, यह अमेरिका वासियों की पुरुष प्रधान मानसिकता को उजागर करता है। ट्रंप ने खुले मंच से घुसपैठियों पर लगाम लगाने एवं स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने की बात कही। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। ट्रंप के प्रथम कार्यकाल के दौरान अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते अच्छे रहे थे। उम्मीद है कि इस कार्यकाल में रिश्तों में मजबूती आएगी।

हिमांशु शेखर, गया

बेहतर हो लास्ट माइल कनेक्टिविटी

वेशक, दीपावली पर पटाखों के वैन की धज्जियां उड़ती दिखाई दीं समूची दिल्ली में लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना कि पटाखों पर 12 महीने वैन लगना चाहिए ठीक नहीं है। कारण, हवा में जहर घोलने में पटाखों के अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, आसपास के राज्यों में पराली का जलना सभी शामिल हैं। इन कारणों पर गंभीरता से विमर्श और कार्रवाई हो। स्टेकहोल्डर्स दिल्ली, आसपास के प्रदेश, केंद्र सरकार आदि सभी की राय ली जाए। सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली की हवा को अत्यधिक खतरे वाली श्रेणी में पहुंचने ही न दिया जाए। आखिरी मील कनेक्टिविटी बेहतर की जाए ताकि जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाए।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
उत्तरोत्तर • उत्तरोत्तर • उत्तरोत्तर

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कायदी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा फ्लाई तल, सहारा इण्डिया बिहार, बेलेरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

वर्ष - 19, अंक 6477 आर.एन.आई. नं. बीआईएचएसआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

दैनिक जागरण
किसी चीज को दबाना उसे शक्ति देने का दूसरा नाम है

बुलडोजर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर दिशानिर्देश जारी करके यह सुनिश्चित करने का काम किया कि अतिक्रमण, अवैध निर्माण के साथ-साथ अपराध के खिलाफ मनमानी कार्रवाई न होने पाए। ऐसा किया जाना आवश्यक था, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई अपराध में लिप्त तत्वों के खिलाफ भी होती थी और इस आधार पर होती थी कि उन्होंने अपना मकान, दुकान या अन्य कोई इमारत अवैध रूप से बना रखी है। शासन-प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करने में इसलिए आसानी होती थी, क्योंकि प्रायः लोग अपने भवनों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र या तय मानकों के हिसाब से नहीं कराते। बुलडोजर कार्रवाई को इसलिए जनता का समर्थन मिलता था, क्योंकि उसकी यह आकांक्षा रहती है कि अपराधी तत्वों को यथाशीघ्र दंड मिले। इसी कारण बुलडोजर कार्रवाई की सराहना होती थी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस तरह की कार्रवाई में संदिग्ध अपराधी-अभियुक्त का घर-दुकान ध्वस्त होने से उसके स्वजन भी सजा पाते थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी आरोपित की सजा उसके परिवार वालों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो दिशानिर्देश जारी किए, उनके आधार पर इस बात से तो पर्दा पड़ ही नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता बंद होने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों से यह स्पष्ट है कि अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नोटिस भेजने और मामले की सुनवाई करने के बाद बुलडोजर कार्रवाई संभव है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को व्याख्या इस रूप में भी की जा रही है कि इससे माफिया तत्वों और पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। देखना है कि ऐसा होता है या नहीं? जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर अतिक्रमण हटाने और जमीनों पर कब्जे रोकने पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह अपराधी तत्वों का दुस्साहस भी नहीं बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि बिना फैसले किसी को दोषी न माना जाए और अपराधी को दंड देना अदालत का काम है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अदालतें यह काम सही तरह से कर पा रही हैं? अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट पर इस प्रश्न पर भी गौर करता, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि अपराधी और माफिया तत्वों को उनके किए की सजा मुश्किल से ही मिलती है। मिलती भी है, तो बहुत विलंब से। बाहुबली, धनबली किस्म के या फिर राजनीतिक असर वाले अपराधी तत्वों के मामलों में यही अधिक देखने को मिलता है कि वे अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को लंबा खींचने में सफल हो जाते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि संगीन अपराध में लिप्त तत्वों को भी शीघ्र सजा नहीं मिल पाती। इसी कारण लोग बुलडोजर कार्रवाई को न्याय की संज्ञा देते हैं। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट यह देख पाता कि बुलडोजर कार्रवाई न्याय में देरी की उपज है।

जनहित में सही निर्णय

पंजाब सरकार आखिरकार केंद्रीय फंड लेने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना आम आदमी क्लीनिक का नाम बदलने के लिए तैयार हो ही गई। वैसे भी राज्य की जनकल्याण की योजनाओं के लिए केंद्रीय फंड की अधिक आवश्यकता होती है। पंजाब पर इस समय साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज भी है। ऐसे में लोगों के कल्याण की योजनाएं तभी शुरू हो सकती हैं या सुचारु रूप से जारी रह सकती हैं, जब राज्य और केंद्र सारे मनमुटाव भूलकर मिलकर काम करें। राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य लोगों का कल्याण ही होना चाहिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के साढ़े छह सौ करोड़ रुपये इसीलिए रोके थे, क्योंकि पंजाब सरकार ने योजना का नाम ही बदल दिया था। जनहित की योजनाएं तभी सफलतापूर्वक चलेंगी जब केंद्र और राज्य के बीच खींचतान नहीं होगी। पंजाब में अभी 872 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं, जहां लोगों को घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल रही है। अब इसमें से करीब चार सौ क्लीनिकों के आगे से आम आदमी शब्द और मुख्यमंत्री का फोटो हटेगा। वैसे भी केंद्र सरकार की आर्थिक मदद के बिना कोई भी राज्य जनकल्याण के कार्य जारी नहीं रख सकता है। इसका एक कारण यह है कि राज्यों के पास आमदनी के स्रोत बहुत सीमित होते हैं। राज्यों को जीएसटी और अन्य मदों से ही आय अर्जित होती है। राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य प्रदेश की जनता के लिए अधिक से अधिक राहत की योजनाएं शुरू करना ही होना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, उसे राजनीति से अधिक समाजसेवा को महत्व देना चाहिए।

लोगों के कल्याण की योजनाएं तभी शुरू हो सकती हैं या सुचारु रूप से जारी रह सकती हैं, जब राज्य और केंद्र मिलकर काम करें

एएमयू पर एक और फैसले की प्रतीक्षा

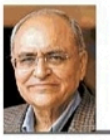

बलबीर पुंज

आखिर सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान में एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लेना चाहिए?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का निहितार्थ क्या है? शीर्ष अदालत की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 1967 के फैसले को 4-3 से पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। यह स्थापित सत्य है और स्वयं एएमयू की आधिकारिक वेबसाइट में इसका उल्लेख है कि यह विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान का विचारबीज है। 17 अक्टूबर, 1817 को जन्मे सर सैयद अहमद खान 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों की सहायता की। उनका बिरसा जीतकर वह 1867-76 के बीच ब्रिटानी अदालत में न्यायाधीश रहे। अप्रैल 1869 में सर सैयद को इंग्लैंड में 'आर्ट्स आफ द स्टार आफ इंडिया' से नवाजा गया, तो 1887 में लार्ड डफरिन ने उन्हें 'सिविल सेवा आयोग' का सदस्य बना दिया। 'खान बहादुर' नाम से प्रख्यात सर सैयद की वफादारी से प्रमुदित ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें 1898 में 'नाइट' की उपाधि दी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना के साथ देश में पूर्ण स्वतंत्रता और लोकतंत्रीय व्यवस्था की मांग उठनी शुरू हुई, तब ब्रितानियों के प्रति निष्ठावान सर सैयद ने मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 'हिंदू-मुस्लिम', 'हिंदी-उर्दू', 'संस्कृत-फारसी' का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की मजहबी भावनाओं के जरिये विचार स्थापित किया कि मुसलमान का कर्तव्य है कि वह अंग्रेजों के निकट और कांग्रेस से दूर रहे। इस अभियान में वह काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय मुख्यधारा, चेतना से कट चुका था और कालांतर में वह पाकिस्तान के लिए आंदोलित भी हुआ। इस चिंतन का सूत्रपात सर सैयद ने 16 मार्च, 1888 को मेरठ में यह भाषण देकर किया, ''सोचिए यदि अंग्रेज भारत में नहीं हैं, तो कौन शासक होगा? क्या दो राष्ट्र-हिंदू और मुसलमान एक सिंहासन पर बराबर के अधिकार से बैठ सकेंगे? नहीं। आवश्यक है कि उनमें से एक, दूसरे को पराजित करे। आखिर सात से सालों तक भारत में आपका साम्राज्य रहा है। आप जानते हैं कि शासन करना क्या होता है। मुसलमानों का सच्चा मित्र केवल ईसाई ही हो सकते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था अपनानी होगी, जिससे अंग्रेज भारत में हमेशा के लिए राज कर सकें और सत्ता कभी भी 'बंगालियों' के हाथों में न जाए।''

सर सैयद कांग्रेस के नेताओं को अक्सर 'बंगाली' कहकर तिरस्कृत करते थे, क्योंकि तब अधिकांश कांग्रेसी नेतृत्व बंगाल से था। अपनी इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में सर सैयद ने 1875-77 के दौरान अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम और मुस्लिम-एंग्लो ओरिएंटल कालेज की स्थापना की, जिसे उनके निधन के 22 वर्ष बाद तत्कालीन ब्रितानी सरकार ने 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय' का स्वरूप दिया। एएमयू का मूल उद्देश्य क्या था? 1930-33 में पाकिस्तान का खाका खींचने के बाद एएमयू मुस्लिम लीग का अनौपचारिक राजनीतिक-वैचारिक प्रतिष्ठान बन गया। एएमयू छात्रसंघ ने कांग्रेस को फासीवादी बताते हुए 1941 में मजहब आधारित विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। जिन्ना ने 10 मार्च, 1941 को एएमयू को 'पाकिस्तानी आयुधशाला' बताया, तो उसी वर्ष अगस्त में एएमयू छात्रों को संबोधित करते हुए लियाकत अली खान (पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री) ने कहा, ''हम मुस्लिम राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए आपको उपयोगी गोला-बारूद के रूप में देख रहे हैं।'' कालांतर में हुए चुनावों में एएमयू के छात्रों-शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर मुस्लिम लीग का समर्थन किया।

अशोक राजपूत

जो मुस्लिम नेता (मौलाना आजाद और प्रो. हुमायूं कबीर आदि) तब विभाजन का विरोध कर रहे थे, उन पर एएमयू छात्रों ने मजहब का शत्रु मानते हुए हमला किया। विभाजन और स्वाधीनता पश्चात अपेक्षा थी कि या तो एएमयू बंद होगा या फिर इसके आधारभूत चिंतन में परिवर्तन आएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 22 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया। इसके एक दिन पहले तक एएमयू छात्र पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो रहे थे। इसकी भनक लगते ही यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी और विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया। अगस्त 1956 में एएमयू छात्रों ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए। एएमयू 2018 में भी अपने 'जिन्ना प्रेम' के कारण विवादों में था।

स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं (स्वाधीनता सहित) और एएमयू के घोषित एजेंडे के बीच टकराव था। जब शेष भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था, तब एएमयू सर सैयद के 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' को मूर्त रूप दे रहा था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में एक अलग इस्लामी देश-पाकिस्तान को जन्म दिया। एएमयू के इस चरित्र से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. नेहरू भी परिचित थे। 24 जनवरी, 1948 को एएमयू के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए नेहरू ने कहा था, ''...मुझे अपनी विरासत और अपने पूर्वजों पर गर्व है, जिन्होंने भारत को बौद्धिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता प्रदान की। आप इस अतीत पर कैसा अनुभव करते हैं? ...हमारे मजहब अलग-अलग हो सकते हैं, किंतु यह उस सांस्कृतिक विरासत से वंचित होने का कारण नहीं बन जाता, जो आपकी भी है और मेरी भी।''

आजादी के बाद स्वतंत्र भारत ने हाशिये पर पड़े समाज के उन वर्गों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा, जिन्होंने ऐतिहासिक अन्याय झेला था। ऐसे परिमार्जन के लिए सकारात्मक और दृढ़ कदम उठाते हुए संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रविधान किया गया। कांग्रेस सहित स्वयंभू सेक्युलरवादियों की अनुकंपा से एएमयू लगातार समाज के इन दोनों वर्गों समेत ओबीसी को भी संवैधानिक अधिकार देने से इन्कार करता रहा। यक्ष प्रश्न यह है कि स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान में एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? यह वह प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। देखना है कि एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय नई पीठ क्या फैसला करती है?

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

समस्याओं के हल की राह देखते शहर

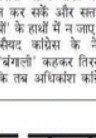

हितेश वैद्य

शहरी ढांचे में सुधार के लिए अनगिनत समितियों, रपटों और नीतियों के निर्माण के बावजूद हालात जस के तस हैं

समस्याओं से घिरते शहरों नागरिक। प्रेट्र

बहुत पहले एक कहानी सुनी थी, जिसमें एक मां अपने बच्चों को केवल यह भरोसा दिलाने के लिए पत्थरों का सूप बनाने का अभिनय करती है कि जल्द ही उनकी भूख मिट जाएगी। इसके लिए वह चूल्हे पर रखे पानी के बर्तन में पड़े पत्थरों को चम्मच से हिलाती रहती है। आज अपने देश में शहरी विकास की चुनौतियों से निपटने के तौर-तरीकों को देखने पर लगता है कि हमारे नीति नियंताओं द्वारा शहरों के विकास के नाम पर पत्थरों का सूप बनाने की कोशिश जारी है। हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं, जहां योजनाओं का निर्माण और सुधार की प्रक्रिया सूप बनाने के इसी अभिनय में सिमट गई है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी शहरी विकास की भूख कब मिटेगी? शहरी ढांचे में सुधार के लिए अनगिनत रिपोर्ट, समितियां और नीतियें के निर्माण के बावजूद हालात जस के तस ही हैं। इसे देखते हुए शहरी विकास के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाने का समय आ गया है, पुराने तौर-तरीकों से अब काम नहीं चलेगा। वैसे हमारे पास शहरी विकास के लिए योजनाओं और नीतियों की कमी नहीं है। सचिवों की समिति, राष्ट्रीय शहरी नीति, इंडिया हैबिटेट-3 रिपोर्ट, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी रिफार्म रिपोर्ट और हाल में अमृतकाल की राह के रूप में अन्य कई रिपोर्ट इसके गवाह हैं। अब जरूरत है कि हम इन योजनाओं पर अमल करें और अपने शहरों को वास्तव में बदलें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी विकास की जरूरत पर जोर देते हुए जलवायु परिवर्तन और सर्कुलर इकोनमी की बात कही है। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपने बजट भाषण में शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में रूपांतरित करने की जरूरत जता चुकी हैं। शहरों का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ इमारतें और सड़कें ही नहीं बनतीं, बल्कि लोगों के जीवन भी बदलते हैं। भारत में तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के साथ हमें यातायात जाम, प्रदूषण और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शहरी विकास के लिए हमें सभी पहलुओं-आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश, पर्यावरण संरक्षण और लोगों की भागीदारी को समग्र रूप से देखना चाहिए, ताकि शहरों का विकास समावेशी, टिकाऊ और सभी के लिए फायदेमंद हो। समस्या यह है कि जमीन पर वास्तविक काम करने के बजाय अभी भी रस्मअदायगी की जा रही है। यह गत दिनों यूएन हैबिटेट ग्लोबल स्टेट आफ नेशनल अर्बन पालिसी (एनयूपी) की रिपोर्ट में हमारी अनुपस्थिति से साफ नजर आया। 78 देशों ने अपना शहरी दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे अधिक शहरी आबादी वाला देश भारत का पन्ना खाली रहा। हम इस मामले में और अधिक देरी सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। शहरों के सिस्टम एवं नेटवर्क में सुधार, समावेशी विकास, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला, कार्य क्षमता एवं निगरानी तथा आकलन, इन्फ्रास्ट्रक्चर का वित्त पोषण, आर्थिक विकास, कौशल और नवाचार एनयूपी की एक साझा थीम रही। हम भी इन मोर्चों पर बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और हमारी तमाम रपटों में ये विषय प्रमुखता से उठे हैं। सवाल है कि आखिर हम इन मामलों में विश्लेषण के दौर से आगे बढ़ने और स्ष्ठी मायने में काम शुरू करने में हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं? क्यों हम केवल प्रतीकात्मक सुधारों से ही संतुष्ट हैं और ठोस प्रगति करने के बजाय केवल छानबीन करने के उपायों में ही लगे हैं? इस रवैये से तो यही लगता है कि हम बड़े सुधार शुरू करने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव से जूझ रहे हैं अथवा हमें एजेंसियों के बीच समन्वय कायम करने के तौर-तरीके ही नहीं सूझ रहे हैं।

आज जरूरत अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करने की है। समय आ गया है जब हम प्रतीकात्मक कामकाज करने के बजाय स्पष्ट नजर आने वाली प्रगति की दिशा में काम करें। इससे भी अधिक जरूरत यह है कि हम सबसे पहले शहरी सुधार के लिए आवश्यक पहलों और उनके पीछे के संपूर्ण परिदृश्य को भलीभांति समझ लें। निःसंदेह इनमें से तमाम अच्छी भावना के साथ शुरू की गई हैं, लेकिन यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि इनके पीछे जो दृष्टिकोण है, उसका लक्षित वर्ग क्या है, उनसे क्या लाभ होने हैं? यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि हर कोई यह महसूस कर रहा है कि केवल कागजी और कोरी बातों से काम चलने वाला नहीं है। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कुछ ठोस न करने की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस निष्क्रियता के दुष्परिणामों की आज हमारे शहर भोग रहे हैं। हमारे शहरों की क्षमता और उनकी सौंधापना ही समाप्त होती नजर आ रही है। लोगों का भरोसा टूट रहा है कि हम जरूरी शहरी सुधार करने की वास्तविक इच्छाशक्ति रखते हैं। शहरों के ढांचे में सुधार की इच्छाशक्ति का अभाव दूर होना आवश्यक है।

हमें शहरी विकास के लिए एक ऐसे एकीकृत राष्ट्रीय विजन की जरूरत है, जो स्थानीय सरकारों को शक्तियां दे और लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहन प्रदान करने का काम करे और हमारा ध्यान उनके क्रियान्वयन पर होना चाहिए, न कि समितियां गठित करने के अंतहीन सिलसिले पर। भारत का शहरी भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम शहरीकरण प्रक्रिया को कितना प्रभावशाली और नतीजे देने वाली बना पाते हैं। हमारे पास ज्ञान, संसाधनों और क्षमता की कमी नहीं है। इस सबके साथ यदि कुछ और सबसे अधिक जरूरी है तो वह है जेहन में काम करने की ललक पैदा करना। हमें ऐसे शहर बनाने होंगे, जो अपने नागरिकों का पूरी तरह खयाल रखने में सक्षम हों।

(लेखक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विनम्रता

विनम्रता ऐसा गुण है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक उसी तरह शोभित करता है जैसे शरीर में आभूषण। विनम्रता का अर्थ है-स्वभाव में लचीलापन की उपस्थिति। इस गुण की सार्थकता व्यक्ति एवं समाज अथवा एक व्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंधों एवं व्यवहार के आधार पर ही सिद्ध हो सकती है। एकाकी रूप से बैठे हुए किसी मनुष्य के अंदर विनम्रता का गुण खोज पाना नितांत दुरूसाध्य कार्य है। विनम्रता एक ऐसा रत्न है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व में छिपा रहता है। इसके अन्वेषण के लिए व्यक्तित्व का मंथन ठीक उसी तरह अनिवार्य है।

किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के मंथन के लिए उसकी समझना नितांत आवश्यक है। वहीं किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमें उसके साथ ऐसे संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, जो परस्पर व्यवहार तथा हृदय एवं मन के संयोग को अभिप्रेरित करें। ऐसे संयोग के उपरांत ही व्यक्तित्व में विनम्रता का स्तर उजागर हो पाता है। विनम्रता का गुण व्यक्ति को व्यक्तित्व में छिपा रहता तो प्रदान करता ही है, साथ ही उसे समाज में भी एक उच्चस्तरीय सम्मान उपलब्ध कराता है। फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका रहता है। यहां पर झुकने का आशय है विनम्र होना और फलों से लदे होने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के अंदर गुणों का समावेश होना। कभी-कभी विनम्रता के गुण को सामाजिक आक्षेपों, तिरस्कारों एवं कटुताओं का भी सामना करना पड़ता है। किंतु ये सभी पारुष प्रभाव सीमित अवधि के लिए ही विद्यमान रहते हैं। अंततोगत्वा विनम्रता व्यक्तित्वरूपी आकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकती है। हमें विनम्रता के गुण को अपने अंदर आत्मसात करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। किसी भी कार्य की सिद्धि विनम्रता का सहारा लेकर बेहद आसानी से हो सकती है। हमारा मानवजाति में जन्म लेना तभी सार्थक सिद्ध होगा, जब हम आजीवन विनम्र रहें।

प्रेरणा अवस्थी

बच्चों की सुरक्षा के लिए समग्र प्रयास

डा. प्रिया वैष्णव

बच्चों की सुरक्षा के नियमों के बारे में छात्रों, माता-पिता और शिक्षकों को नियमित रूप से जागरूक करना जरूरी है

आज बाल दिवस के दिन आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्या आपको अपने बच्चों के स्कूल की बाल संरक्षण नीति और आनलाइन सुरक्षा नीति के बारे में पता है? क्या आपके बच्चे कठिन विषयों पर आपसे खुल कर बात करते हैं? बच्चों के साथ हिंसा की खबरें सबको बहुत परेशान कर देती हैं, पर बस अफसोस जताने, गुस्सा करने और सख्त सजा की मांग से इस समस्या का हल कभी नहीं निकलेगा।

कक्षा एक से लेकर उच्चतम कक्षाओं तक व्यक्तिगत सुरक्षा एवं सीमाओं के विषय पर पाठ्यक्रम, स्कूल में परामर्श सेवाएं (जहां बच्चे अपनी समस्याओं के बारे में निश्चिंतता से बात कर सकें), अभिभावकों की बराबर भागीदारी, सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे स्कूल अपने बच्चों की सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। सुरक्षा नियमों के बारे में छात्रों, माता-पिता और शिक्षकों को नियमित रूप से जागरूक करना जरूरी है। हर स्कूल में सुरक्षा संबंधित नीतियों के बारे में सत्र होने चाहिए, जहां छात्रों को बिना भय और संकोच के अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन सत्रों में व्यक्तिगत सुरक्षा, शिक्षा और सीमा निर्धारित करने के महत्व के बारे में बात होनी चाहिए। स्कूल के सभी कर्मचारियों, शिक्षकों और समुदाय के लोगों को मिलकर बच्चों के खिलाफ हिंसा से बचाव के लिए चर्चा करनी चाहिए।

स्कूलों में बच्चों के साथ सुरक्षित, असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सुरक्षा की जानकारी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना जरूरी है। स्कूल परिवहन सुरक्षा के नियमों के बारे में माता-पिता, शिक्षकों और परिवहन कर्मचारियों को नियमित रूप से जागरूक करते रहना महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शोषण का सबसे अधिक खतरा होता है। नियमित जागरूकता सत्र, यौन शोषण के संकेतों या किसी भी खतरे के संकेतों पर ध्यान देन इसमें मदद कर सकता है। बच्चों के घर और स्कूल में एक सकारात्मक माहौल उनके सर्वांगीण विकास में मदद करता है। अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों के बीच सकारात्मक एवं स्पष्ट रूप से बातचीत बच्चों को अपनी समस्याओं को साझा करने में मदद करता है। बच्चों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनके साथ हमेशा सख्ती से पेश आना और अनुशासित करने के लिए उन्हें सजा देना ठीक नहीं है। हर परिवार को समझना होगा कि उनका भावनात्मक समर्थन उनके बच्चों को यह भरोसा देता है कि उनका परिवार उनके साथ है। इससे वे खुल कर बात कर पाएंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा। हर परिस्थिति में सतर्क रहना और संवेदनशीलता से काम लेने की जरूरत है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

नासूर बनती घुसपैठ की समस्या

'समस्या पर शेर मचे तो समाधान भी हो' शीर्षक से युक्त आलेख में राजीव सचान ने देश के अंदर होने वाली बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की सुनियोजित अवैध घुसपैठ पर जो चिंता व्यक्त की है, वह केंद्र की मौदी सरकार के लिए विचारणीय विषय बनना चाहिए। अवैध घुसपैठ अब विश्वव्यापी समस्या बन गई है। भारत की तरह ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे अनेक पश्चिमी देश अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे हैं। स्यंभर से भगाए गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की भारतीय सीमा के अंदर अवैध घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय है। इससे न केवल देश के संसाधनों का दोहन हो रहा है अपितु भारत का जनसंख्यिकी संतुलन भी बिगड़ रहा है। स्वतंत्र भारत में जिस तरह से देश के सीमावर्ती राज्यों में आबादी का संतुलन बिगड़ा है उसके मूल में अवैध घुसपैठ ही है। यदि शुरुआती दौर में ही अवैध घुसपैठ को लेकर भारत सरकार द्वारा कड़ाई बरती जाती तो आज यह समस्या देश के लिए नासूर नहीं बनती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के चलते इस राष्ट्रघाती समस्या को पहले की सरकारों द्वारा इसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। 1971 में जिस उदारता से देश की सीमाएं खोल दी गईं थीं उसका दुष्प्रभाव आज नजर आ रहा है। खुशहाल जीवन की आस में बांग्लादेश के मुसलमानों की अवैध घुसपैठ आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन हिंदू बहुल भारत के लिए यह शुभ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम बहुल देशों में अल्पसंख्यक हिंदू-सिखों की जैसी दुर्गति होती है उसका उदहरण पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं। घातक रूप से देश की डेमोग्राफी बदलने वाली अवैध घुसपैठ की इस समस्या पर देश को संकुचित राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

घुसपैठ पर हो कड़ी कार्रवाई

'समस्या पर शेर मचे तो समाधान भी हो' शीर्षक आलेख में राजीव सचान ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या पर चिंता व्यक्त किया है। घुसपैठ की समस्या पर सरकारों का आंख मूंदना खुद एक गंभीर समस्या बन चुका है। भारत में जनसंख्या असंतुलन का मुख्य कारण वोट की निकृष्ट राजनीति का परिणाम है। जिसमें राजनेता वोट के लिए देश को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। डेढ़ अरब की आबादी वाला भारत देश पहले ही जनसंख्या विस्फोट के बुरे दौर से गुजर रहा है। वहीं करोड़ों घुसपैठियों ने देश की जनसंख्या वृद्धि की समस्या के साथ ही देश को जनसंख्या असंतुलन की डरावनी स्थिति में पहुंचा दिया है। एक तरफ बार्डर पर घुसपैठ रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है तो दूसरी तरफ वोट-बैंक के लिए उन्हें बसने के लिए प्रश्रय देने के कुकर्म से भी परहेज नहीं किया जा रहा। इस समस्या को पैदा करने के लिए कमोबेश पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसी तरह इसके निदान के लिए भी दोनों को मिलकर गंभीर बनानी होगी। नहीं तो भविष्य में देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

बेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, उप्र

भाषा की मर्यादा

हास्यास्पद है कि चुनावी समर में महिला सशक्तीकरण की बात हर राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन अनुपालन कोई नहीं करता। हद तब हो गई, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आतंककारी जैसे शब्दों से नवाजा गया। निस्संदेह राजनीति में निजी हमलों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इससे नेताओं की राजनीतिक कुंठा अधिक जिह्वाई देती है। वैसे भी बंदेगी तो कटेंगे का नारा कौन से सौहार्द्रादिक तनाव पैदा करता है? मौलानाओं एवं उलेमाओं द्वारा यह कहना कि मुस्लिम वोट बंटने न पाएं, क्या यह पंथनिरपेक्षता को परिभाषित करता है? झारखंड में नेताओं द्वारा की जा रही राजनीतिक बयानबाजी ने राजनीतिक मर्यादाओं की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। यह निस्संदेह एक गंभीर मंथन का विषय है। देश के नेताओं को राजनीतिक तौर पर संयमित आचरण पर जोर देना होगा। देश विरोधी बाहरी शक्तियों को सबक सिखाना होगा।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जयप्रकाश प्रकाशनार्थ, के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

21,935 क रोड़ रुपये में तय किया था सितंबर 2021 में भारत सरकार ने स्पेन के साथ 56 सैन्य परिवहन विमान सी-295 खरीदने का सौदा। इसमें 16 विमान स्पेन स्थित एएचएस कंपनी तैयार हालत में देगी और शेष 40 उसके सहयोग से भारत में बनाए जाएंगे।

संजय श्रीवास्तव
तकनीकी विषयों के जानकार

सैन्य परिवहन विमान सी-295

विमान निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा देश

युद्ध के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बलों को पहुंचाना हो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में देश के दूरदराज इलाकों तक भोजन एवं पानी जैसी चीजों को अत्यधिक मात्रा में जल्द से जल्द पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में परिवहन विमान बहुत कारगर साबित होते हैं। लिहाजा, केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहल की है, जिसमें टाटा समूह का महत्वपूर्ण योगदान है। उम्मीद की जा रही है कि किसी निजी क्षेत्र द्वारा हवाई जहाज बनाने की यह परिघटना देश के पूरे वैमानिकी के परिदृश्य को बदल सकती है

भारत में मालवाहक विमानों की बढ़ती मांग को देखते हुए यहां भी इसके निर्माण की तैयारी शुरू की जा रही है। प्रतीकात्मक

महान तब विदा लेते हैं, जब आधुनिक और नौजवान उनकी जगह लेने को तैयार होते हैं। वर्ष 1960 में अपनी पहली उड़ान भरने और 1961 से भारतीय वायुसेना की सेवा में लगे ब्रिटेन और एचएएल निर्मित एवरो एचएस-748 अब धीरे-धीरे विदा लेगा, उसकी जगह ले रहा है एयरबस का सी-295। एवरो-748 की छह दशक से ज्यादा की शानदार और विश्वसनीय सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बूढ़ा रहे रूसी मालवाहक एंटोनोव एएन-32 की भी जगह देर सबेर यही लेगा। 25 सितंबर 2023 को जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हिंडन एयरबेस पर पहला सी-295 विमान वायुसेना के 21 राइनो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, तभी यह तय हो गया था कि आगे से हम यह विमान स्वयं बनाएंगे। अब गुजरात के वडोदरा में इसे बनाने लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड या टीएएसएल का प्लांट शुरू हो गया है। फिलहाल यह संयंत्र एयरबस हिफैंस एंड स्पेस कंपनी के सहयोग से सेवा 40 विमान बनाएगा।

टाटा की महत्वाकांक्षी परियोजना : असल में वर्ष 2012 में रतन टाटा ने इस दूरदर्शी परियोजना की परिकल्पना की थी। यह फलीभूत तब हुई जब भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन के साथ 56 सैन्य परिवहन विमान सी-295 खरीदने का सौदा 21,935 करोड़ रुपये में किया। तय हुआ था कि 16 विमान स्पेन के सेविले स्थित एयरबस कंपनी हमें उड़ने के लिए तैयार हालत में देगी और बाकी 40 हम उसके सहयोग से स्वयं बनाएंगे। वर्ष 2022 के अक्टूबर में इसके निर्माण हेतु इस संयंत्र की नींव पड़ी। अब प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इसके उद्घाटन के बाद जब रतन टाटा नहीं हैं, नोएल टाटा के नेतृत्व में कंपनी देश में निजी क्षेत्र के पहला समूचा और अति उन्नत कार्गो हवाई जहाज बनाने के लिए कमर कस चुकी है। टीएएसएल अगस्त 2031 के अंत तक वायुसेना को सभी 40 विमान बनाकर सौंप देगा। इसके बाद 25 बरसों तक भारतीय वायुसेना के इन विमानों की देखरेख का ठेका भी उसी ने ले रखा है। बेशक उसके आगे की भी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं उसके पास हैं।

टीएएसएल और एयरबस मिलकर देश में दूसरे देशों के लिए विमान बनाएंगे। अब वे चाहे युद्धक हों या मालवाही अथवा भविष्य में यात्री विमान। इससे विमान निर्माण के क्षेत्र में बनने वाला परिदृश्य साबित करेगा कि 'मेक इन इंडिया' के साथ 'मेड फार द ग्लोब' और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हम तेजी से बढ़ चले हैं। जल्द ही यूरोपीय और अमेरिकी वर्चस्व वाले एयरोस्पेस मार्केट में भारत एक मजबूत दखल रखेगा। विदेश से आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तो भविष्य में निश्चित रूप से यहां से विमानों के निर्यात के अवसर बनेंगे। इसके अतिरिक्त, रक्षा निर्यात में भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। दुनिया की बड़ी विमान कंपनियों के लिए हम बहुत से कलपुर्जे बनाते ही हैं, परंतु इस नए विमान सी-295 के लिए 18 हजार कलपुर्जे यहीं बनेंगे और आगे चलकर यह घरेलू मांग बढ़ेगी तो नए कौशल और नए छोटे, मंझोले उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। हम बोइंग से हर साल एक अरब अमेरिकी डालर की सेवा लेते हैं। इसमें से 60 प्रतिशत से अधिक विनिर्माण में खर्चते हैं, अब इसमें कमी आएगी। टाटा की सहयोगी कंपनियों, सेकाओं, सैकड़ों हिफैंस स्टार्टअप को भी खूब काम मिलेगा। हमारे देश में एयरोस्पेस इंडस्ट्री आम तौर पर दक्षिण भारत तक सीमित है, अब उसमें विविधता आएगी और देश के अन्य हिस्सों में भी उसका विस्तार होगा। आगरा, कानपुर और प्रयागराज तक इसका विस्तार होगा। टाटा कंसोर्टियम ने सात राज्यों से काम कर रहे सब सौ से अधिक इन-कंट्री एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को काम देने का जो फैसला किया है, वह देश के एयरोस्पेस के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाएगा। यह संयंत्र ही तीन हजार से अधिक लोगों को नौकरी देने वाला है तो वहीं 15 हजार से अधिक लोगों के लिए परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

रखरखाव एवं मरम्मत केंद्र : केंद्र सरकार हो यह प्रयास है कि देश उड्डयन और विमानों के रखरखाव व मरम्मत का केंद्र बन जाए। अब उम्मीद जगी है तो इस पहल के बाद रखरखाव की सुविधा के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, कलपुर्जों के लिए आपूर्ति श्रृंखला तैयार होगी। हैंगर, भवन, एप्रन और टैक्सीवे के साथ ही विशेष बुनियादी ढांचे का विकास होगा। मतलब यह शुरुआत मेंटीनेंस, रिपेयरिंग तथा संचालन यानी एमआरओ की सेवा देने में हमको आगे बढ़ाने वाला है। इन सबके बाद सस्ते श्रम और बेहतर तकनीक सहायता के लिए तमाम विदेशी कंपनियां, संस्थान यहीं आएंगे। आने वाले दो दशकों के भीतर ही देश को लगभग 2500 यात्री और मालवाहक विमानों की जरूरत होगी। यदि हम आत्मनिर्भर बन गए तो सोचिए कितना लाभ होगा। बीते डेढ़ दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए, जिससे भारत में एक बाइब्रेंट हिफैंस इंडस्ट्री का विकास सुनिश्चित हो सका है और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने सरकारी उपक्रमों की प्रभावशाली बनाया। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड का यह हवाई जहाज इसी का उदाहरण है।

सी-295 विमान : वस्तुतः सी-295 के नाम में 'सी' स्पेन की कंपनी कासा यानी सेएएसए का पहला अक्षर है। वैसे अब इसका एयरबस में विलय हो चुका है। '2' बताता है कि इसमें दो इंजन हैं और '95' उसकी भार वहन क्षमता को दर्शाता है। पिछली सदी के अंतिम दशक में यह विमान विकसित हुआ और 28 नवंबर 1997 को इसने पहली उड़ान भरी थी। विमान की लंबाई 80.3 फीट, डैनों का विस्तार 84.8 फीट, ऊंचाई 28.5 फीट है। क्रू केबिन में टचस्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है। यह महज 320 मीटर की दूरी में टेक-आफ और 670 मीटर की दूरी में लैंडिंग कर सकता है। नौ टन वजन के साथ 482 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से यह लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है।

दो प्रैट एंड व्हिटनी टर्बोप्राप इंजन के सहारे यह 30 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके पिछवाड़े रैंप डोर है, मतलब सैनिकों को या सामान को बहुत तेजी से उतारा या चढ़ाया जा सकता है। डैनों के नीचे छह ऐसी जगहें हैं, जहां हथियार और बचाव प्रणाली लगाई जा सके। इसके इनबोर्ड पाइलॉस में 800 किलो के हथियार लगा सकते हैं। आटो रिवर्स क्षमता के चलते यह 12 मीटर चौड़े रनवे पर 180 डिग्री तक मुड़ सकता है। 1500 किलो वजनी रिमूवेबल रीफ्यूलिंग सिस्टम, एक आयस्टेर कैसील और 100 फीट लंबी होज ड्रम तथा तीन अतिरिक्त ईंधन टंकियों से लैस इस विमान को हवा में उड़ता ईंधन टैंकर बनाया जा सकता है। हवा में ही फिक्स्ड विंग वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकाप्टर को ईंधन दिया जा सकता है। यह विमान विभिन्न प्रकार के टोही सेंसर्स आधुनिक एवियोनिक्स से युक्त है। इसका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग संस्करण हवाई क्षेत्र की पूरी तस्वीर देने के लिए अपने राडार से 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है।

भारत के लिए गेमचेंजर साबित होने की उम्मीद

सी-295 विमान प्राकृतिक रूप से हर प्रकार के चुनौतीपूर्ण वातावरण में कामयाब है। ईशोनेशिया, इराक और मिस्र जैसे 37 देशों ने इस विमान को आजमाया है। इसका 'मेड इन इंडिया' और बहुउद्देशीय होना गेम चेंजर साबित होगा। हर मौसम में, रात दिन कभी भी, रेगिस्तान, पहाड़ सभी जगह बहुमुखी प्रतिभा वाला विश्वसनीय सी-295, सामरिक परिवहन विमान अपनी भूमिकाएं निभा सकता है।

यह सैन्य अभियानों के दौरान भार वहन के अलावा भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है। 24 स्ट्रेचर और सत मेडिकल अटेंडेंट ले जाने की सुविधा के साथ इसे उड़ते हुए चिकित्सा घर में बदलने की खूबी हो अथवा सत हजार लीटर पानी के साथ उड़ान में सक्षमता के चलते जंगल की आग से लड़ने के लिए एक कुशल अग्निशामक में बदलना, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके विभिन्न बैरिएंट थोड़े से बदलाव के बाद चिकित्सा उपयोग, जंगलों की आग बुझाने, टोह लेने या हमला करने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। यह विमान सीमित लंबाई वाली हवाई पट्टी से उड़ान भर सकता है और उस पर सुरक्षित उतर भी सकता है। यही नहीं, इसे दैयम दर्जे के कच्चे रनवे से भी उड़ाया और उतारा जा सकता है। इसके अलावा, यह विमान सुरक्षित पैराशूट ड्राप के लिए आवश्यक प्रविधानों से सज्जित है जिसके जरिये सैनिकों तथा हथियारों को दुर्गम स्थानों पर आसानी से और तेजी से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए हवाई हमले और विशेष सैन्य बलों के मूवमेंट के लिए यह अत्यधिक उपयोगी है। सीमा पर चल रही गतिविधियों की दशा में यह क्षमता बड़े काम की है।

समुद्री सीमा पर निगरानी हेतु भी यह आदर्श विमान है। इसका एक बैरिएंट राडार और कई तरह के निगरानी उपकरणों, सेंसर से लैस है जो संकटग्रस्त वायुयान की सहायता, समुद्री गश्त, समुद्री गतिविधियों की निगरानी, समुद्री डकैती से निपटने और उनसे बचाव के लिए उपयोगी है। सैनिकों और सामान को ढोने, दूसरे विमान में तेल भरने और समुद्री गश्त सहित कई तरह के मिशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका एक संस्करण पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है जो सोनोबाय, टारपीडो जैसे उपकरणों से लैस है। सीमा निगरानी मिशन में काम करने और आवश्यकता होने पर सुरक्षा खतरों का जवाब देने में भी यह सक्षम है। सी-295 का इतनी तरह से उपयोग भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बहुमुखी विकल्प देता है। यह तय है कि सी-295 का वायुसेना में समावेश देश की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण बढ़त देगा। इस जहाज का परिचालन और रखरखाव सस्ता है, से इसे प्रशिक्षण के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। (संजय श्रीवास्तव)

खरी-खरी

काम नहीं बोलता है...

इंद्रजीत कौर

दिन-रात काम में खटने के बाद शांति से बैठ जाना, काम के बारे में एक शब्द भी न बोलना पूरी तरह गलत है। स्वयं के साथ अन्याय है। यह काम न करने के बराबर ही माना जाता है। बहुत लोग तो बैठे-बिठाए ही काम का डंका पीट देते हैं। टीवी के एक विज्ञापन की याद आती है कि बिस्कुट में काजू है तो दिखना भी चाहिए, न दिखे तो यही मानना चाहिए कि उसमें काजू है ही नहीं। यही बात वास्तविक जीवन में भी फिट बैठती है। काम किया है तो शोर मचना ही चाहिए। किसी को एक रुपया भी दिया है तो चिल्लाकर, नारे लगाकर और कीर्तन करके पूरे ब्रह्मांड को बताने में देर नहीं करना चाहिए। भले एक रुपये के चक्कर में पांच रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

लेकिन मुझमें यह खराब आदत है। किसी के लिए एक कप चाय भी बनानी हो तो बनाकर पीने वाले के आगे चुपचाप रख दूंगी, पर मेरी बहन थोड़ी सुधरी हुई है। वह चाय बनाने से पहले, बनाते समय, छानते हुए और पेश करते समय का सीधा प्रसारण तेज आवाज में करती है। 'मैं चाय बनाने जा रही हूं', 'बर्तन धो रही हूं', 'अब चाय गैस पर रख दी है', 'छान रही हूं', 'ला रही हूं', 'पी लीजिए', 'आराम से पीजिए' के मीठे बोल चलते रहते हैं। इतना ही नहीं, चाय खत्म होने के बाद 'अच्छी चाय बनी हो तो कितना अच्छा लगता है,' जैसे आध्यात्मिक बोल बोलकर चाय का विज्ञापन स्वयं ही कर देती है।

यही हाल आजकल कुछ कुछ देश का लग रहा है। योजनाएं कितनी भी आएं-जाएं, जमीन पर दिखें या न दिखें, शोर ऐसा मचता है कि धरती हिल जाती है। ऐसे बात नहीं कि काजू को पीस कर बिस्कुट में नहीं डाला जा सकता। इसका स्वाद खाने में पता चल ही जाता है और ताकत आती है सो अलग। लंबे समय तक शरीर के लिए फायदेमंद भी रहता है, पर जो दिखता है, वही बिकता है। काजू की जगह मूंगफली के ही टुकड़े क्यों न हों? मूंगफली की जगह काजू का ही बजट क्यों न मिला हो? शांति से कार्य करने वालों के नाम तो इतिहास में भी दर्ज नहीं होते। कितना ही कोई कह दे कि काम ही बोलता है, बिखराव मत करिए। कर्म करें या न करें, कर्म का ढोंड जरूर होना चाहिए।

पोस्ट

सिग्नलरेलेड में बुर्का पर पाबंदी का फैसला एक जनवरी, 2025 से लागू होगा। अब समय आ गया है कि पूरे विश्व में बुर्का प्रतिबंधित किया जाए।
तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शानदार है। अब किसी का भी अवैध कब्जा तोड़ने से पहले सरकार/प्रशासन को कानून दुरुस्त रखने होंगे। यही होना भी चाहिए।
हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लातूर में नितिन गडकरी के हेलिकाप्टर की चेकिंग हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरह उन्होंने न अधिकारियों को धमकाया, न ही उसका वीडियो बनाकर पोस्ट किया, बल्कि छुट्टी कर रहे चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया।
अमन चोपड़ा@AmanChopra_

साल 1991 के आर्थिक सुधारों के बावजूद भारत में शासन व्यवस्था में नौकरशाही और लालफीताशाही अभी भी बहुत ज्यादा है। भारत को भी अमेरिका की तरह डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग की जरूरत है।
मोनिका वर्मा@TrulyMonica

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दीवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध से वायु प्रदूषण रोकने में मदद मिल सकी है?

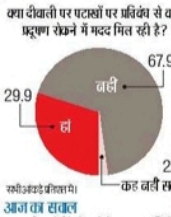

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग बंदिनहीं जाएगा?

परिणाम जागरण डॉट कम पर संस्करण के पहले का माह है।

जनपथ

कट्टरता पर मजहबी चुप रह जाते लोग,
क्योंकी उनके वोट का करना है उपभोग।
करना है उपभोग रोग है यह स्वार्थी,
नहीं दिखे इस रोग हेतु अब कोई दवाई।
खतरनाक यह ट्रेड इसी से दिल है डरता,
हमें आज किस ओर जा रही ले कट्टरता!
- ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

कांग्रेस से आए नेताओं के कारण भाजपा में असंतोष

संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में भाजपा मजबूत स्थिति में इसलिए है, क्योंकि अनुशासन और समर्पण को उसने मंत्र बना रखा है। बड़ा नेता हो या आम कार्यकर्ता, सबके लिए अनुशासन की डोर में बंधे रहने की अनिवार्यता है। परंतु हाल के दिनों की कुछ घटनाएं भाजपा को चेतावनी दे रही हैं। रीगन्ठन को विस्तार देने के प्रयासों ने अनेक जिलों में ऐसी विभाजन रेखा खींच दी है कि संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती है। स्वयं को विजेता बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने दूसरे दलों, खासकर कांग्रेस के नेताओं को शामिल करने का बड़ा अभियान चलाया था।

भाजपा ने जिस जोर-शोर से कांग्रेस नेताओं को शामिल कराने का अभियान चलाया, अब वही विवाद का कारण बन रहा है। कांग्रेस से भाजपा में आए अनेक नेता राज्य स्तर से लेकर जिलों तक में महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुके हैं। कई तो राज्य सरकार में मंत्री बनाए जा चुके हैं। उनके प्रभाव के कारण स्थानीय राजनीति में भाजपा के अनेक पुराने एवं नए नेताओं व कार्यकर्ताओं का प्रभाव-संतुलन बिगड़ने लगा है। कई जिले तो ऐसे हैं, जहां ये नेता एक-दूसरे की टांग-खिंचाई में लगे हैं। इसका ताजा मामला सागर जिले में सामने आया है, जहां कांग्रेस से आए नेताओं एवं पुराने भाजपा नेताओं में असहमतियां एक-दूसरे के विरोध के स्तर तक पहुंच चुकी हैं। हाल ही में सागर में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह कहकर विवाद को सार्वजनिक कर दिया कि कांग्रेस से आए नेताओं को भले ही भाजपा स्वीकार कर ले, लेकिन

भूपेंद्र सिंह। फाइल

वह स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी टिप्पणी अपने ही जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं राज्य सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बारे में मानी जा रही है, जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। गोविंद सिंह राजपूत पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री थे और अब मात्र ढाई हजार मतों के अंतर से जीतने के बाद भी डा. मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं।

गोविंद सिंह राजपूत। फाइल

वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति में शिवराज के बाद पिछड़ी जाति के बड़े चेहरे के रूप में माने जाते रहे भूपेंद्र सिंह लंबे समय बाद सरकार से बाहर हैं। एक समय तो यह तक चर्चा होने लगी थी कि यदि शिवराज को मध्य प्रदेश से केंद्र में ले जाया जाता है तो भूपेंद्र विकल्प बन सकते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि वह प्रदेश में मंत्री तक नहीं बन सके। इससे स्थानीय राजनीति व प्रशासन में गोविंद सिंह राजपूत का महत्व बढ़ा है। कई मामलों को लेकर भूपेंद्र सिंह एवं राजपूत के समर्थकों में विवाद-टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त करने में देर नहीं की। उन्होंने स्थानीय भाजपा के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए साफ कर दिया कि कांग्रेस से आए नेताओं को भले ही हमारी पार्टी स्वीकार करे, लेकिन हम नहीं करेंगे।

हालांकि भूपेंद्र सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने मंत्री रहते अपने विधानसभा क्षेत्र खुरई को कांग्रेस विहीन करने का अभियान चला रखा था। कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को भाजपा में शामिल कराकर क्षेत्र को लगभग कांग्रेस विहीन करने का डंका बजा दिया था। स्थिति यह हो गई थी कि निकाय चुनावों में कांग्रेस को कई सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं मिले। अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेता ही उन्हें खटकने लगे हैं। दीपावली मिलन समारोह के कुछ ही दिन पूर्व भूपेंद्र ने सागर में विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने भी यह कहकर हलचल मचा दी थी कि स्थानीय पुलिस भाजपा नेताओं के फोन रिकार्ड करके दबाव बना रही है। उप मुख्यमंत्री ने इस पर हैरानी जताई और कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। जिला प्रशासन के अधिकारियों में भी सफाई दी और कहा कि वे इस आरोप की जांच करेंगे।

मतलब यह कि अंदरखाने मामला इस कदर गहरा गया है कि प्रदेश संगठन के लिए भी असहज स्थिति बन सकती है। भूपेंद्र के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी यह कहकर पलटवार किया है, 'यदि सागर का कोई नेता पार्टी से ऊपर हो गया है और कह रहा है कि भाजपा में आने वाले कांग्रेसियों को पार्टी स्वीकार करे तो करे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा।' ऐसे में यह शीर्ष नेतृत्व के लिए विचार का प्रश्न है।

स्मरण

देश पर सर्वस्व अर्पण करने वाले नायक

महज 25 वर्ष की उम्र में ही बिरसा मुंडा ने देश के लिए इतना त्याग किया कि वे सदा के लिए अमर हो गए। अपने जीवन की चिंता न करते हुए देश और समाज के लिए अपना सबकुछ न्यौछावर करने वाले ऐसे महापुरुष निश्चितही पूजनीय हो जाते हैं

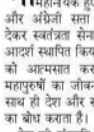

ऋचा सिंह
सामाजिक मामलों की जानकार

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महानायक हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों और अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नया आदर्श स्थापित किया। भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने वाले ऐसे कई महापुरुषों का जीवन प्रेरणाप्रद होने के साथ ही देश और समाज को राष्ट्रीयता का बोध कराता है।

देश की संस्कृति, परंपरा एवं धरोहर की रक्षा की बात की जाए तो जनजातीय समाज का स्थान अग्रिम पंक्ति में आता है। भारत की आजादी की लड़ाई में सैकड़ों जनजातीय बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता दिलाई। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, जहां जनजातियों ने अंग्रेजों से लोहा न लिया हो। धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा ऐसे ही एक नायक थे जिन्होंने देश-समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के साथ बिरसा मुंडा ने भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश सरकार के विरोध में ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसने समाज को जागरूक करने के साथ ही अंग्रेजों को भारत की भूमि छोड़ने पर विवश कर दिया।

उलगुलान : भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी एवं मुंडा जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसीडेंसी में हुए आदिवासी धार्मिक-सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के साथ अपने अनुयायियों के बीच 'धरती आबा' के तौर पर पूजे जाने लगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के ध्वजवाहक बिरसा मुंडा छोटानागपुर के क्षेत्र में अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुए संघर्ष में भारतीय जनमानस को शोषण मुक्त शासन के लिए एकजुट कर जन, जंगल, जमीन, आजादी और अस्मिता के लिए आवाज उठाने (उलगुलान) हेतु आवाहन किया। स्वाधीनता की लड़ाई में जनजातीय समाज के द्वारा किए गए बलिदान, शौर्यपूर्ण संघर्ष तथा उनके गौरवशाली परंपरा एवं वीरता के विषय में लोग जान सकें, इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस'' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था।

समतावादी व्यवस्था : इंडियन फारेस्ट एक्ट 1882 पारित करके अंग्रेजों ने वनवासियों एवं आदिवासियों के गांव, जहां वह खेती करते थे, उसमें नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। इसके पहले मुंडा जनजाति में भूमि कोई विक्रय की वस्तु नहीं थी, न ही भूमि पर खेती के लिए कर देय था। मुंडाओं में भूमि समतावादी व्यवस्था के अनुसार सभी को समान रूप से मिली थी। बिरसा ने ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 1899 में बिगुल फूंक दिया। इस प्रकार मुंडा उलगुलान शुरू हुआ। बिरसा ने अंग्रेजी सरकार के शोषण के विरुद्ध आंदोलन की शुरूआत की। वैसे अपने शिष्यों को एकत्र करते हुए मुंडा ने उन्हें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए 1894 में ही उलगुलान की घोषणा से अपने जंगल, जमीन पर अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। मुंडा समुदाय ने अंग्रेजी राज को समाप्त करने का निर्णय लिया।

बिरसा ने 'अबुआ दिशुम अबुआ राज' यानें 'हमारा देश, हमारा राज' का नारा देकर अपने समुदाय के लोगों को इस आवाहन से जागरूक किया। मुंडा के इस आवाहन से सभी आदिवासी अपने जमीन एवं जंगल पर दावेदारी के लिए संगठित हो गए जिससे अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे। अंग्रेजी सरकार ने मुंडा उलगुलान को दबाने और दमन करने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन मुंडा समाज के एकजुट संघर्ष एवं शौर्य के आगे वह असफल रहे। वर्ष 1897 से 1900 के बीच आदिवासी मुंडाओं ने संगठित होकर अंग्रेजों से कई युद्ध किए और उन्हें वहां से उखड़ने पर मजबूर कर दिया। मुंडा आंदोलन संगठित एवं उग्र था। अपनी अस्मिता के लिए प्रखर था। परिणामतः हर बार अंग्रेजों को मुंहकी खानी पड़ी। बिरसा को मुंडाओं ने अपना भगवान 'धरती आबा' मान लिया था, जिनके एक आवाहन पर मुंडा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपने प्राण भी देने को तैयार थे।

15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती पर ही झारखंड राज्य का गठन किया गया। इनकी जयंती 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाई जाती है, जिसके माध्यम से लोगों को जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, वीरता और शौर्य को जानने का अवसर प्राप्त हो सके। स्वाधीनता की लड़ाई में उनके द्वारा किए गए बलिदान, शौर्य और संघर्ष को समाज सदैव याद रखेगा। मुंडा समाज के दिलों में सदा के लिए अपना नाम अंकित करके बिरसा ने वह हासिल किया जिसे हासिल करने में एक लंबी उम्र भी कम पड़ जाती है, उससे अधिक बिरसा मुंडा ने अपनी महज 25 वर्ष की उम्र में कर लिया और छोटी उम्र में बड़ी जिंदगी जीकर 'धरती आबा' बन कर इतिहास में अमर हो गए।

बिरसा मुंडा की मूर्ति। फाइल

****